

द्रुथ पथ



ड्रीफ न्यूज

आईएमए पासिंग आउट पर-
ड शनिवार को, 16 मित्र देशों
के साथ 515 जेंटलमैन
कैडेट भरेंगे 'अतिम पग'

देहरादून, (एजेंसी) : देहरादून स्थित भारतीय सैन्य अकादमी (आईएमए) में शनिवार को होने वाली पासिंग आउट परेड (पीओपी) राष्ट्रीय गौरव और वैश्विक सैन्य सहयोग का प्रतीक बनेगी। परेड में कुल 515 जेंटलमैन कैडेट अतिम कदम बढ़ाएंगे, जिनमें 481 भारतीय कैडेट और 16 मित्र देशों के 34 विदेशी कैडेट शामिल हैं। परेड की समीक्षा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू करेंगी, जो दो दिवसीय दौर पर देहरादून पहुंच चुकी हैं।

पासिंग आउट परेड के साथ ही 481 भारतीय कैडेट भारतीय सेना में अधिकारी के रूप में अपनी नई जिम्मेदारियां संभालेंगे, जबकि 16 मित्र देशों के 34 विदेशी कैडेट भी प्रशिक्षण पूर्ण कर अपने-अपने देशों की सेनाओं में सेवाएं देंगे। आईएमए से प्रशिक्षित अधिकारी दुनिया के अनेक देशों की सेनाओं में महत्वपूर्ण दायित्व निभा रहे हैं, जिससे यह संस्थान अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सैन्य नेतृत्व तैयार करने के प्रमुख केंद्रों में गिना जाता है।

राष्ट्रपति के दौरे और परेड को देखते हुए राजधानी देहरादून में सुरक्षा व्यवस्था अभूतपूर्व स्तर पर की गई है।

मोदी और मैक्रों 14 जून को फ्रांस में करेंगे भारत इन्वेस्ट्स का उद्घाटन

नई दिल्ली, (एजेंसी) : प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति एमैनुएल मैक्रों 14 जून को फ्रांस के नीस में ह्यभारत इन्वेस्ट्स 2026 का संयुक्त रूप से उद्घाटन करेंगे। शिक्षा मंत्रालय की इस पहल का उद्देश्य भारत के डीप-टेक स्टार्टअप, नवाचार और अनुसंधान क्षमता को वैश्विक निवेशकों तथा उद्योग जगत के सामने प्रस्तुत करना है।

शिक्षा मंत्रालय ने शुक्रवार को बताया कि कार्यक्रम में भारत के 120 नवप्रवर्तक, 15 से अधिक उच्च शिक्षण संस्थान, 500 से अधिक निवेशक, प्रमुख कॉर्पोरेट कंपनियां, चूंख कैपिटल फर्म, वैश्विक मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) और उद्योग जगत के नेता भाग लेंगे। इसमें एड-वॉर्स क्यूएलटी, सेमीकंडक्टर, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, जैव-प्रौद्योगिकी, ऊर्जा, स्वास्थ्य सेवा और डिजिटल सहित 13 प्रमुख क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी के साथ विदेश मंत्री एस. जयशंकर और वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल के भी कार्यक्रम में शामिल होने की संभावना है।

भाजपा ने भारतीय राजनीति में भरोसे के संकट को किया दूर : राजनाथ सिंह

देहरादून, (एजेंसी) : रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शुक्रवार को सिकंदराबाद में आयोजित विकसित भारत संकल्प सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि राजनीति में किसी भी नेता की सबसे बड़ी पूंजी उसकी विश्वसनीयता होती है और यदि भारतीय राजनीति में भरोसे के संकट को किसी दल ने दूर किया है तो वह भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) है। हाल के चुनावों में जनता ने उन लोगों को करारा जवाब दिया है जिन्होंने उसका विश्वास तोड़ा।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व का उल्लेख करते हुए राजनाथ सिंह ने कहा कि सरकार ने भ्रष्टाचार के खिलाफ स्पष्ट नीति अपनाई है और यह तय किया गया है कि न तो सरकार भ्रष्टाचार करेगी और न ही किसी को करने दिया जाएगा। काँग्रेस पर निशाना साधते हुए राजनाथ सिंह ने कहा कि उसके शासनकाल में कई बड़े घोटाले सामने आए, जिनमें कोयला घोटाला, 2जी घोटाला और कॉमनवेल्थ घोटाला शामिल हैं, जिनसे देश को भारी आर्थिक नुकसान हुआ। रक्षा मंत्री ने कहा कि देश के रक्षा क्षेत्र में बड़ा परिवर्तन देखने को मिल रहा है। उन्होंने कहा कि डीआरडीओ, रक्षा सर्वजनिक उपक्रम, निजी उद्योग, स्टार्टअप, एमएसएमई और शिक्षा जगत अब पहले से अधिक समन्वय के साथ काम कर रहे हैं।

केंद्र की पूर्वोत्तर में बड़े बदलाव की तैयारी: 2027 तक हटेगा अफसपा

असम-नागालैंड सीमा पर फिर शुरू होगा तेल-गैस उत्पादन

नई दिल्ली (एजेंसी) : केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने पूर्वोत्तर भारत के लिए दो महत्वपूर्ण घोषणाएं कीं, जो क्षेत्र में शांति और विकास की नई दिशा देंगी। उन्होंने बताया कि वर्ष 2027 तक एक-दो राज्यों को छोड़कर पूरे पूर्वोत्तर से सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम (अफसपा) हटाया जाएगा। इसके साथ ही, केंद्र सरकार, असम और नागालैंड के बीच सीमा विवाद वाले क्षेत्र में लंबे समय से बंद पड़ा तेल और गैस उत्पादन फिर से शुरू करेगी। केंद्रीय गृह मंत्री शाह ने इस निर्णय के पीछे पूर्वोत्तर में सुरक्षा कमी को प्रमुख कारण बताया। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में विभिन्न शांति समझौतों के सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं, जिससे क्षेत्र में स्थायी शांति की बहाली संभव हुई है। अफसपा के दायरे में लगातार की जा रही कटौती



इसी प्रगति का प्रमाण है। केंद्रीय गृह मंत्री ने उम्मीद जाहिर की कि यदि कानून-व्यवस्था की वर्तमान स्थिति बनी रहती है, तब अगले वर्ष तक अधिकांश क्षेत्रों से यह कठोर कानून हटा दिया जाएगा। वहीं ऊर्जा क्षेत्र से जुड़ी दूसरी बड़ी घोषणा कर शाह ने बताया कि केंद्र सरकार तथा असम और नागालैंड की सरकारों के बीच सीमा विवाद वाले उस क्षेत्र में तेल और गैस उत्पादन फिर से

शुरू करने पर सहमति बनी है, जो लंबे समय से विवाद और प्रशासनिक चुनौतियों के कारण निष्क्रिय पड़ा हुआ था। केंद्र सरकार का अनुमान है कि इस क्षेत्र में 15,000 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य के तेल और गैस भंडार मौजूद हैं। उत्पादन शुरू होने के बाद, क्षेत्र की तेल उत्पादन क्षमता वर्तमान 1,000-1,500 बैरल प्रतिदिन से बढ़कर करीब दस गुना तक पहुंच सकती है। इस परियोजना

से न केवल देश की ऊर्जा आत्मनिर्भरता बढ़ेगी, बल्कि स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर पैदा होने और क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी। केंद्र सरकार का मानना है कि शांति, सुरक्षा और आर्थिक विकास के ये कदम पूर्वोत्तर भारत को देश की विकास यात्रा में एक अधिक प्रभावी और गतिशील भूमिका निभाने में सक्षम बनाएंगे।

भारत-बांग्लादेश सीमा वार्ता संपन्न: घुसपैठ और सीमा सुरक्षा पर सीधी चर्चा

नई दिल्ली, (एजेंसी) : नई दिल्ली में भारत और बांग्लादेश के बीच सीमा सुरक्षा से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर आयोजित चार दिवसीय महानिदेशक (डीजी) स्तर की महत्वपूर्ण वार्ता संपन्न हुई। इस बैठक में सीमा पर बढ़ते तनाव, अवैध घुसपैठ, सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) के जवानों पर हमलों और सीमा बाड़ की क्षति पहुंचाने जैसी घटनाओं पर चर्चा की गई।

यह 57वां महानिदेशक स्तरीय सम्मेलन था, जो नई दिल्ली स्थित बीएसएफ मुख्यालय में बार्डर सिन्डिकेटिड फार्स (बीएसएफ) और बार्डर गार्ड बांग्लादेश (बीजीबी) के महानिदेशकों के बीच आयोजित हुई। भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व बीएसएफ के महानिदेशक प्रवीण कुमार ने किया, जबकि बांग्लादेशी प्रतिनिधिमंडल की अगुवाई बीजीबी के महानिदेशक मोहम्मद अशरफुज्जामा सिद्दीकी ने की। वार्ता के दौरान भारत ने सीमा पार से होने वाली अवैध घुसपैठ, बांग्लादेशी नागरिकों द्वारा बीएसएफ कर्मियों और भारतीय नागरिकों पर हमलों, तथा सीमा पार लगी बाड़ को नुकसान पहुंचाने जैसे



मामलों को अत्यंत गंभीरता से उठाया। बीएसएफ प्रमुख कुमार ने इन मुद्दों को प्राथमिकता के साथ संबोधित कर सीमा पर शांति और सुरक्षा बनाए रखने की अनिवार्यता पर जोर दिया। बैठक का एक उल्लेखनीय पहलू यह रहा कि संयुक्त दस्तावेज पर हस्ताक्षर होने के बाद भी दोनों देशों के महानिदेशकों की पारंपरिक संयुक्त प्रेस वार्ता आयोजित नहीं की गई, इस सीमा वार्ता के इतिहास में एक असाधारण घटनाक्रम माना जा रहा है। यह वार्ता राजनीतिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण थी, क्योंकि बांग्लादेश में इस वर्ष की शुरूआत में नई सरकार के गठन और पश्चिम

बांग्ला में सत्ता परिवर्तन के बाद दोनों देशों के सीमा सुरक्षा बलों के बीच यह पहली औपचारिक उच्चस्तरीय बैठक थी। भारत और बांग्लादेश के बीच लगभग 4,096 किलोमीटर लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा है, जिसमें से 2,216 किलोमीटर हिस्सा पश्चिम बांग्ला से होकर गुजरता है। ऐसे में सीमा प्रबंधन, अवैध गतिविधियों की रोकथाम और द्विपक्षीय सहयोग दोनों देशों के लिए सदैव महत्वपूर्ण रहे हैं। दोनों पक्षों ने सीमा पर शांति, सुरक्षा और बेहतर समन्वय बनाए रखने के लिए संवाद जारी रखने तथा आपसी सहयोग को और मजबूत करने पर सहमति व्यक्त की। पिछली बैठक ठाका में हुई थी।

मीनाक्षी नटराजन को सुप्रीम कोर्ट से करारा झटका

-चुनावी प्रक्रिया में हस्तक्षेप से किया इनकार, याचिका खारिज

-नामांकन रह होने के खिलाफ पहुंची थीं शीर्ष अदालत

नई दिल्ली, (एजेंसी) : सुप्रीम कोर्ट ने काँग्रेस नेता मीनाक्षी नटराजन को बड़ा झटका देते हुए उनकी याचिका खारिज कर दी है। राज्यसभा चुनाव के लिए उनका नामांकन रद्द किए जाने के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए शीर्ष अदालत ने स्पष्ट किया कि एक बार चुनावी प्रक्रिया शुरू हो जाने के बाद न्यायालय के हस्तक्षेप की सीमाएं निर्धारित हैं और इस चरण में अदालत चुनाव प्रक्रिया में दखल नहीं दे सकती। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि उसने याचिकाकर्ता की सभी दलीलों पर विचार किया है। याचिका में दावा किया गया था कि रिटर्निंग ऑफिसर (आरओ) ने यह कहते हुए नामांकन खारिज कर दिया कि उम्मीदवार ने अधूरा फॉर्म भरा था। अपने खिलाफ लॉबिंग शिकायत मामले की जानकारी नहीं दी। याचिकाकर्ता का कहना था कि संबंधित मामले में न तो आरोप तय हुए थे और न ही अदालत ने संज्ञान लिया था, इसलिए ऐसी जानकारी न देने के आधार पर नामांकन रद्द करना मनमाना और अवैध है। सुनवाई के दौरान यह भी बताया गया कि आरओ के आदेश के खिलाफ निर्वाचन आयोग का रुख किया गया था। याचिकाकर्ता ने लिखित आवेदन देने के साथ आयोग के समक्ष व्यक्तिगत रूप से अपना पक्ष भी रखा, लेकिन आयोग ने कोई आदेश पारित नहीं किया। मामले में याचिकाकर्ता की ओर से संविधान के अनुच्छेद 329(बी) तथा पूर्व के न्यायिक निर्णयों का हवाला देते हुए कहा गया कि उनकी याचिका का उद्देश्य चुनाव



प्रक्रिया को बाधित करना नहीं, बल्कि उसे निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से जारी रखना है। वहीं निर्वाचन आयोग और मध्य प्रदेश सरकार की ओर से वरिष्ठ अधिकारियों ने याचिका की ग्राह्यता पर ही प्रश्न उठाया। उनका तर्क था कि चुनाव लड़ना मौलिक नहीं बल्कि वैधानिक अधिकार है और नामांकन रद्द होने की स्थिति में एकमात्र कानूनी उपाय चुनाव याचिका दायर करना होता है। मामले की प्रथम मंथन में मध्य प्रदेश की राज्यसभा सीट का चुनाव है। जांच के दौरान मीनाक्षी नटराजन के नामांकन पत्र में कथित रूप से एक आपराधिक मामले की जानकारी छिपाने का आरोप सामने आया था। इसके बाद उनका नामांकन निरस्त कर दिया गया। भाजपा उम्मीदवार महेश केवट ने इस संबंध में आपत्ति दर्ज कराई थी। नामांकन रद्द होने के बाद राज्य की तीसरी राज्यसभा सीट पर मुकाबला समतल हो गया और महेश केवट के निर्विरोध निर्वाचित होने का रास्ता साफ हो गया।

ईंधन संकट: अब 200 लीटर से ज्यादा नहीं खरीद पाएंगे डीजल

नई दिल्ली (एजेंसी) : देशभर में पेट्रोल और डीजल की संभावित किल्लत को रोकने और आपूर्ति व्यवस्था को सुचारु बनाए रखने के लिए केंद्र सरकार ने एक बेहद सख्त और बड़ा कदम उठाया है। नए सरकारी आदेश के तहत, अब सामान्य पेट्रोल पंपों से इंडस्ट्रियल (औद्योगिक) और कर्मशियल (व्यावसायिक) उपभोक्ताओं द्वारा पेट्रोल-डीजल खरीदने पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है। अब ऐसे बड़े उपभोक्ताओं को अपनी जरूरत का ईंधन केवल अधिकृत बल्क सप्लायर (थोक आपूर्ति केंद्रों) से ही खरीदना होगा। सरकार ने फिलहाल इस कड़े प्रतिबंध को 90 दिनों की अवधि के लिए लागू किया है, हालांकि स्थिति में संतोषजनक सुधार होने पर इसे तय समय से पहले भी वापस लिया जा सकता है।

सरकार को यह कदम इसलिए उठाना पड़ा क्योंकि अब तक कई बड़ी ट्रांसपोर्ट कंपनियां और औद्योगिक इकाइयां निर्धारित बल्क डिपो से ईंधन खरीदने के बजाय सीधे खुदरा पेट्रोल पंपों का रुख कर रही थीं। इसकी मुख्य वजह खुदरा और थोक कीमतों के बीच



का भारी अंतर था। उदाहरण के लिए, दिल्ली में जहां आम खुदरा पेट्रोल पंप पर डीजल की कीमत 95.20 रुपये प्रति लीटर है, वहीं थोक (बल्क) ग्राहकों के लिए यही डीजल 134.50 रुपये प्रति लीटर की दर से मिल रहा है। कीमतों में प्रति लीटर करीब 39 रुपये का यह बड़ा अंतर होने के कारण बड़ी कंपनियां खुदरा पंपों से भारी मात्रा में डीजल खरीद रही थीं, जिससे कड़े क्षेत्रों में ईंधन की कमी की स्थिति बनने लगी थी। इसके अलावा, पश्चिम एशिया में

सरकारी तेल कंपनियों के इस आर्थिक नुकसान को कम करने, जमाखोरी रोकने और देशभर में ईंधन की समान उपलब्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से ही यह आपातकालीन नियंत्रण व्यवस्था लागू की गई है।

घरेलू उपभोक्ताओं को घबराने की जरूरत नहीं। इस बड़े फैसले के साथ ही सरकार ने खुदरा पेट्रोल पंपों पर डीजल की बिक्री को लेकर एक दैनिक सीमा (डेली लिमिट) भी निर्धारित कर दी है। नए नियमों के मुताबिक, अब किसी भी सामान्य खुदरा पेट्रोल पंप से एक ग्राहक या एक वाहन को एक दिन में अधिकतम केवल 200 लीटर डीजल ही जारी किया जा सकेगा। सरकार ने इस बात को पूरी तरह स्पष्ट किया है कि इस कदम से सामान्य वाहन चालकों और घरेलू उपभोक्ताओं को घबराने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। आम जनता के लिए पेट्रोल और डीजल की नियमित सप्लाय पूरी तरह सामान्य बनी रहेगी, क्योंकि यह फैसला मुख्य रूप से बड़े व्यावसायिक और औद्योगिक उपभोक्ताओं को ध्यान में रखकर लिया गया है।

भोपाल में रहकर पाकिस्तान के इशारे पर कर रहा था अफगानिस्तान में अंशाति फैलाने की तैयारी

केंद्रीय जांच एजेंसी से मिले इनपुट पर एटीएस ने पुराने शहर से सड़िध को किया गिरफ्तार-पाक से भेजे गए कथित देश विरोधी दस्तावेज बरामद

विशेष ट्रेनिंग के लिए अफगानिस्तान जाने की तैयारी में था युवक

भोपाल (एजेंसी) : राजधानी भोपाल की एटीएस ने पुराने शहर के हनुमानगंज थाना इलाके में स्थित काजी कैफ क्षेत्र से एक ऐसे सड़िध पाकिस्तानी आंतकी संगठन से जुड़े एजेंट को गिरफ्तार किया है, जो भोपाल में रहकर पाकिस्तानी आंतकी संगठन के इशारे पर अफगानिस्तान में अंशाति फैलाने की तैयारी में जुटा था। सड़िध युवक बीते काफी समय से पाकिस्तानी आंतकी संगठन के संपर्क में था। सूत्रों के मुताबिक युवक के लगातार पाकिस्तानी एजेंट से संपर्क में रहने पर इसकी भनक केंद्रीय जांच एजेंसी को लग गई। इसके बाद भोपाल एटीएस ने केंद्रीय जांच एजेंसी से मिले इनपुट के आधार पर उसे



गिरफ्तार कर लिया। लोकल सूत्रों के अनुसार पकड़ाये गये युवक का नाम मोहम्मद फराज बताया गया है, जो काँग्रेस नगर में रहते हुए एक डॉक्टर के क्लिनिक पर काम करता है। टीम ने इनपुट मिलने के बाद घेराबंदी कर उसे नगर निगम कॉलोनी के पास से गिरफ्तार किया है। उस पर देश-विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप है। विभागीय सूत्रों के मुताबिक युवक को पाकिस्तानी आंतकी संगठन के

नेटवर्क से जुड़े होने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। सूत्र बताते हैं कि शुरूआती जांच में उसके कब्जे से पाकिस्तान से भेजे गए कथित देश विरोधी दस्तावेज भी बरामद किए गए हैं। वहीं यह भी पता चला है, की पकड़ाया गया आरोपी युवक कथित तौर पर विशेष ट्रेनिंग के लिए अफगानिस्तान जाने की तैयारी कर रहा था। जानकारी के मुताबिक आरोपी मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग भी ले रहा था। जांच एजेंसियों को

उसके उत्तर प्रदेश के देवबंद मंदरसे से जुड़े कुछ संपर्कों की भी जानकारी मिली है, जिसे लेकर आगे की पड़ताल की जा रही है। फिलहाल एजेंसी उससे पूछताछ कर उसके लोकल नेटवर्क सहित स्थानीय और विदेशी संपर्कों के साथ ही उसके द्वारा की जा रही संभावित गतिविधियों की जांच में जुटी है। जांच एजेंसी आरोपी को कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लेकर आगे की पूछताछ करने की तैयारी है।

मनु भाकर के कोच जसपाल राणा नहीं रहे

नई दिल्ली (एजेंसी) : भारतीय खेल जगत के लिए शुक्रवार का दिन एक बेहद दुखद और स्वस्थ करने वाली खबर लेकर आया। देश के महान निशानेबाज और विख्यात कोच जसपाल राणा का 49 वर्ष की आयु में आकस्मिक निधन हो गया है। पिछले सप्ताह अचानक तबीयत बिगड़ने के बाद उनका इलाज चल रहा था, लेकिन तमाम प्रयासों के बावजूद उन्हें बचाया नहीं जा सका। राष्ट्रीय राष्ट्रफल संघ ने उनके असाधारण निधन की आधिकारिक पुष्टि की है। उनके जाने से भारतीय खेल जगत, विशेषकर शूटिंग विरादरी में गहरे शोक की लहर दौड़ गई है और इसे खेल इतिहास के लिए एक अपूरणीय क्षति माना जा रहा है। राणा के कोचिंग करियर का स्वर्णिम अध्याय देश की स्टाer निशानेबाज मनु भाकर के साथ जुड़ा रहा।

उन्होंने मनु के करियर के सबसे महत्वपूर्ण और संवेदनशील दौर में उनके खेल को एक नया आयाम दिया। उनके कुशल मार्गदर्शन और गहन प्रशिक्षण का ही परिणाम था कि मनु भाकर ने वर्ष 2024 के पॉस ऑलिंपिक में इतिहास रचते हुए महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल और मिक्सटे टीम 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धाओं में दो ऐतिहासिक कांस्य पदक जीतकर देश



का नाम रोशन किया। जानकारी के अनुसार, जसपाल राणा वर्तमान में भारतीय पिस्टल निशानेबाजों के हाई-परफॉर्मंस कोच के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे थे। पिछले हफ्ते म्यूनिख, जर्मनी में आयोजित हुए आईएसएसएफ वर्ल्ड कप में भाग लेकर जब भारतीय दल स्वदेश लौट रहा था, तब उड़ान में भर्ती कराया गया, जहां उनकी आवश्यक चिकित्सा प्रक्रियाएं पूरी की गईं और चिकित्सकों की देखरेख में उनका सचन उपचार चल रहा था। दुर्भाग्यवश, उपचार के दौरान उन्होंने अंतिम सांस ली। जसपाल राणा का जाना भारतीय

निशानेबाजी के लिए एक युग का अंत माना जा रहा है। उन्होंने तीन दशकों से भी अधिक समय तक एक उत्कृष्ट खिलाड़ी और मार्गदर्शक के रूप में खेल की सेवा की। 1990 के दशक में अंतरराष्ट्रीय मंच पर भारतीय निशानेबाजी का परचम लहराने वाले राणा देश के सबसे सफल पिस्टल शूटर्स में से एक थे। उन्होंने एशियाई खेलों, राष्ट्रमंडल खेलों और एशियाई चैंपियनशिप में अनेक स्वर्ण और रजत पदक जीतकर वैश्विक स्तर पर भारत का दबदबा कायम किया था। उनकी इन बेमिसाल जीतों ने भारत में निशानेबाजी को एक बेहद लोकप्रिय खेल बनाने में क्रांतिकारी भूमिका निभाई और देश के लाखों युवाओं को इस खेल से जुड़ने की प्रेरणा दी।

संक्षिप्त खबरें

गेतलसूद सोलर प्रोजेक्ट के बेस कैम्प में ग्रामीणों का प्रदर्शन, सेकी को सौंपा गया मांग पत्र



द्रुथ पथ प्रतिनिधि
रांची : गेतलसूद डैम के अंतर्गत निमाणाधीन सोलर पावर परियोजना से प्रभावित आक्रोशित ग्रामीणों ने शुक्रवार को गेतलसूद स्थित सेकी के बेस कैम्प में रोषपूर्ण प्रदर्शन किया। ग्रामीणों का आरोप था कि सेकी के सीएसआर फंड का लगातार दुरुपयोग किया गया है, फर्जी बिल बनाकर करोड़ों रुपए की बंदरबांट की गई है। यहां बिचौलिये हावी है। ग्रामीणों ने स्थानीय विकास और विस्थापितों के अधिकारों को पहली प्राथमिकता देने की मांग की। मुफ्त बिजली देने की मांग रखी इस दौरान विस्थापित संघर्ष समिति के बैनर तले ग्रामीणों ने सेकी प्रबंधन को ज्ञापन सौंपा मीके पर मुख्य रूप से प्रमुख दीपा उरांव, पूर्व प्रमुख अनिता गाड़ी, मुखिया शांति मुंडा, जितेंद्र उरांव, अजय उरांव, कामेश्वर महतो, सूरज उरांव, कृष्णा महतो, जयेश्वर महतो, गौरीशंकर मुंडा, हरिनंदन गोस्वामी, राजेश लोहरा, बिदू उरांव, चंदन गोस्वामी, विवेक गोस्वामी, सुधीर महतो, राजन महतो, गणेश करमाली, सत्येंद्र मुंडा सहित भारी संख्या में अंदोलित ग्रामीण उपस्थित थे। उल्लेखनीय है कि गेतलसूद में सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के खिलाफ लगातार ग्रामीणों का आक्रोश बढ़ रहा है, बिचौलियों के हावी रहने एवं सीएसआर मद की राशि का बंदरबांट करने का आरोप लगाकर ग्रामीण क्रमबद्ध अंदोलन कर रहे हैं। विगत 18 मई को भी यहां घेराव व प्रदर्शन किया गया था, इसके बाद अंचल कार्यालय में आयोजित बैठक में भी सेकी के अधिकारी सीएसआर मद में खर्च की गई राशि का विवरण नहीं दे सके थे। ग्रामीण पूर्व में दिए गए ज्ञापन पर किसी प्रकार कार्रवाई नहीं होने से ज्यदा नाराज हैं।

राजपाल से जनहित मुद्दों को लेकर मिला भारत आदिवासी पार्टी



द्रुथ पथ प्रतिनिधि
रांची : राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार से शुक्रवार को भारत आदिवासी पार्टी, पश्चिमी सिंहभूम के जिला अध्यक्ष सुशील बाडुला के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने लोक भवन में भेंट की तथा विभिन्न जनहित से जुड़े विषयों पर ज्ञापन सौंपा। प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल का ध्यान पश्चिमी सिंहभूम जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट चाइबासा के कार्यों में कथित अनियमितताओं की ओर आकृष्ट करते हुए मामले की उच्च स्तरीय जांच झारखंड उच्च न्यायालय की निगरानी में कराये जाने के लिए पहल करने का आग्रह किया। ज्ञापन में उल्लेख किया गया कि संविधान की पांचवीं अनुसूची के अंतर्गत अधिसूचित एवं खनिज संपदा से समृद्ध पश्चिमी सिंहभूम जिले में खनिज प्रभावित क्षेत्रों के समग्र विकास के उद्देश्य से जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट में बड़ी राशि उपलब्ध है, लेकिन इसके बावजूद अनेक प्रभावित क्षेत्रों में शुद्ध पेयजल, शिक्षा, स्वास्थ्य, कौशल विकास एवं अन्य आधारभूत सुविधाओं का अपेक्षित लाभ स्थानीय लोगों तक समुचित रूप से नहीं पहुंच पा रहा है। ज्ञापन में विशेष रूप से मनोहरपुर प्रखंड के राजस्व ग्राम लाइलोर में स्थापित जलापूर्ति योजना का उल्लेख करते हुए कहा गया कि इसके माध्यम से नौ गांवों के लोगों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जाना था, लेकिन पाइपलाइन का कार्य पूर्ण नहीं होने के कारण ग्रामीण आज भी दूषित जल के उपयोग को विवश हैं। प्रतिनिधिमंडल द्वारा सारंडा वन क्षेत्र में वर्ष 2005 से पूर्व से निवास कर रहे लोगों को वनाधिकार अधिनियम -2006 के प्रावधानों के अनुरूप वनाधिकार पट्टा प्रदान करने तथा उन्हें संविधान प्रदत्त मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने की दिशा में आवश्यक पहल किये जाने का भी अनुरोध भी किया।

विश्व रक्तदाता दिवस के सफल क्रियान्वयन को लेकर सीएस की अध्यक्षता में हुई बैठक



द्रुथ पथ प्रतिनिधि
खूंटी : सिविल सर्जन खूंटी के सभागार में विश्व रक्तदाता दिवस के सफल क्रियान्वयन हेतु सिविल सर्जन डॉ ललित रंजन पाठक की अध्यक्षता में खूंटी नगर पंचायत के सम्मानित अध्यक्ष रानी टूटी, उपाध्यक्ष शशांक शेखर एवं निर्वाचित सभी वार्ड पार्षदों के साथ कार्यशाला आयोजित किया गया। कार्यशाला का शुभारंभ सिविल सर्जन एवं नगर पंचायत अध्यक्ष रानी टूटी के द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। अपने संबोधन में सिविल सर्जन डॉ ललित रंजन पाठक ने बताया कि आगामी 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस मनाया जाएगा इस वर्ष कार्यक्रम का थीम है वन ड्रॉप ऑफ़ ह्यूमनिटी, गिव ब्लाड सेव्स लाइव्स, मानवता की एक बूंद रक्तदान करे जीवन बचाये। उन्होंने बताया कि खूंटी जिले में थैलीसीमिया पीड़ित मरीजों एवं दुर्घटना मरीजों, गर्भवती महिलाओं एवं एनीमिया से पीड़ित बच्चों एवं बुजुर्गों को समय समय पर रक्त की आवश्यकता पड़ती है। अतः जिले के रक्तकोष में रक्त की कमी को देखते हुए रक्तदान हेतु जनभागीदारी सुनिश्चित करने की आवश्यकता है। उन्होंने उपस्थित वार्ड पार्षदों से अपने अपने वार्ड में रक्तदान शिविर लगाने के लिए प्रेरित किए। नगर पंचायत अध्यक्ष रानी टूटी ने बताया कि रक्तदान महादान है इसमें आम नागरिक के साथ साथ जनप्रतिनिधि को भी रक्तदान के क्षेत्र में आगे आना चाहिए। उन्होंने सभी पार्षदों को रक्तदान के लिए आगे आने के लिए कहा। जिला आरसीएच पदाधिकारी डॉ शोभा किशोरा ने बताया कि गर्भवती महिलाओं को एनीमिया से मुक्त होने के लिए नियमित आइरन एवं कैल्शियम गोली खाने हेतु जागरूक करने की आवश्यकता है। कार्यक्रम के पश्चात उपस्थित सभी वार्ड पार्षदों को रक्तदाता दिवस के अवसर पर शपथ ग्रहण कराया गया एवं वार्ड पार्षदों का रक्तदान शिविर लगाने हेतु सभी वार्ड पार्षदों को ब्लड डोनेशन कैलेंडर वितरित किया गया।

द्रुथ पथ के लिए प्रकाशक एवं मुद्रक कुमार भारती के द्वारा डी.बी. कॉर्प लिमिटेड, भास्कर प्रिंटिंग प्रेस गोविंदपुर मेन रोड, अशोक नगर के.जी. आश्रम, धनबाद (झारखंड) से मुद्रिक एवं नियर भाटिया शिव मंदिर, गांधी नगर धनबाद से प्रकाशित फोन नं. 7004605076, 9852421580

संपादक:- रवि रंजन * इस अंक में प्रकाशित समाचार के चयन एवं सम्पादन हेतु पी आर वी एक्ट की धारा 7 के अंतर्गत उतरदायी। ई. मेल:-truthpath941@gmail.com आर. एन. आई. नंबर . -JHAHIN/2023/90593

विश्व बाल श्रम निषेध दिवस के अवसर पर डीएलएसए पारा विधिक स्वयंसेवकों का क्षमता संवर्धन एवं जागरूकता कार्यक्रम आयोजित

द्रुथ पथ प्रतिनिधि
सरयकेला : झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, रांची के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, सरयकेला-खरसावां द्वारा विश्व बाल श्रम निषेध दिवस के अवसर पर पारा विधिक स्वयंसेवकों (पीएलवी) के लिए क्षमता संवर्धन कार्यक्रम सह जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में पारा विधिक स्वयंसेवकों, विभिन्न विभागों के पदाधिकारियों, हितधारकों तथा बाल अधिकार एवं विधिक सहायता से जुड़े व्यक्तियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। कार्यक्रम का उद्देश्य पारा विधिक स्वयंसेवकों की क्षमता में वृद्धि करना तथा बाल श्रम की समस्या, बच्चों के संरक्षण हेतु उपलब्ध कानूनी प्रावधानों एवं बाल श्रमिकों के पुनर्वास संबंधी व्यवस्थाओं के प्रति जागरूकता उत्पन्न करना था। कार्यक्रम में संबोधित करते हुए श्री तौसीफ मेराज, सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, सरयकेला-खरसावां ने बाल अधिकारों का हनन करना बाल श्रम से संबंधित विभिन्न कानूनी पहलुओं पर विस्तारपूर्वक प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि बाल श्रम बच्चों के मौलिक अधिकारों का हनन करता है तथा उनके शारीरिक, मानसिक, शैक्षणिक एवं सामाजिक विकास को गंभीर रूप से प्रभावित करता है। उन्होंने पारा



विधिक स्वयंसेवकों की भूमिका को अत्यंत महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि वे बाल श्रम की पहचान, पीड़ित बच्चों को विधिक सहायता उपलब्ध कराने तथा उनके पुनर्वास में महत्वपूर्ण कड़ी का कार्य करते हैं। उन्होंने बच्चों के संरक्षण हेतु उपलब्ध विभिन्न सरकारी योजनाओं एवं विधिक सहायता तंत्र की जानकारी देते हुए कहा कि बाल श्रम उन्मूलन के लिए सरकार, विधिक सेवा संस्थाओं, शैक्षणिक संस्थाओं एवं समाज के सभी वर्गों को मिलकर कार्य करना होगा। अपने संबोधन के दौरान श्री तौसीफ मेराज ने बाल श्रम में संलग्न व्यक्तियों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई संबंधी प्रावधानों की भी विस्तृत जानकारी

दी। उन्होंने बताया कि बाल एवं किशोर श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम, 1986, कारखाना अधिनियम, खान अधिनियम तथा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21ए, 24, 39(ई) एवं 39(एफ) बच्चों को श्रम से सुरक्षा प्रदान करते हैं तथा उन्हें शिक्षा, स्वास्थ्य, सम्मान और समुचित विकास का अधिकार सुनिश्चित करते हैं। उन्होंने कहा कि बाल श्रम में संलग्न पाए जाने वाले किसी भी व्यक्ति, नियोक्ता, प्रतिष्ठान अथवा संगठन के विरुद्ध कानून अनुसार कठोर कार्रवाई की जा सकती है। बाल श्रमिकों को नियोजित करने वाले नियोक्ता को छह माह से तीन वर्ष तक के कारावास तथा 20,000 से 50,000 रुपए तक के जुर्माने अथवा दोनों से दंडित किया जा सकता है। उन्होंने सभी हितधारकों से अपील की कि वे बाल श्रम की किसी भी घटना की सूचना तत्काल संबंधित प्राधिकारियों को दें ताकि प्रभावित बच्चों का शीघ्र उद्धार एवं पुनर्वास सुनिश्चित किया जा सके। कार्यक्रम में उपस्थित परिबीक्षाधीन उप समाहर्ता नवीन कुमार बाड़ा एवं विष्णु मुंडा ने भी प्रतिभागियों को संबोधित किया। उन्होंने बाल श्रम के सामाजिक, आर्थिक एवं कानूनी पहलुओं पर विस्तार से चर्चा करते हुए कहा कि बाल श्रम उन्मूलन में सामुदायिक भागीदारी अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने पारा विधिक स्वयंसेवकों से अपने-अपने कार्यक्षेत्र में जागरूकता फैलाने तथा बाल श्रम की घटनाओं की सूचना संबंधित अधिकारियों तक पहुंचाने का आह्वान किया। कार्यक्रम के दौरान प्रतिभागियों को बाल श्रम से बचाने के लिए प्रत्येक बच्चे को शिक्षा, सम्मान, सुरक्षा एवं स्वस्थ बचपन का अधिकार प्राप्त है। कार्यक्रम के अंत में शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें उपस्थित सभी प्रतिभागियों ने बाल श्रम उन्मूलन हेतु सक्रिय रूप से कार्य करने तथा बाल श्रम की किसी भी घटना की जानकारी प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से प्राप्त होने पर संबंधित अधिकारियों को सूचित करने की शपथ ली। सभी ने बच्चों के अधिकारों की रक्षा एवं बाल श्रम मुक्त समाज के निर्माण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। कार्यक्रम का समापन बाल श्रम उन्मूलन, बच्चों के अधिकारों के संरक्षण तथा उनके सुरक्षित, सम्मानजनक एवं उज्वल भविष्य के निर्माण के सामूहिक संकल्प के साथ हुआ।

ग्रामीणों के शिकायत पर देर रात रेंगनिया पहुंचे वित्त मंत्री, अवैध मिट्टी उत्खनन में लगे एक पोकलेन व तीन ट्रेलर को कराया जब्त

द्रुथ पथ प्रतिनिधि
पलामू : वित्त मंत्री सह स्थानीय विधायक राधाकृष्ण किशोर प्रखंड क्षेत्र के रेंगनिया गांव में देर रात्रि पहुंचे। उक्त गांव में जीएम लैंड भूमि से मिट्टी मोरम में अवैध उत्खनन में किया जा रहा है। मंत्री के निर्देश पर उक्त स्थल से अवैध रूप से मिट्टी मोरम उठाव कर रहे तीन ट्रेलर व एक पोकलेन को जब्त कराया। इस मामले की शिकायत स्थानीय ग्रामीणों ने मंत्री श्री किशोर से किया था। प्रशासन को भी सूचना दी गई थी, लेकिन प्रशासनिक कार्रवाई नहीं होने से लोगों में आक्रोश था। प्रखंड क्षेत्र के गोसा-

ईडीह, रगनियां आदि गांवों पिछले दो वर्ष से अंतरराज्यीय गिरोह के द्वारा अवैध उत्खनन किया जा रहा था। मिट्टी को बिहार के कई जिलों में भेजा जा रहा था। क्षेत्र में लगभग 300 एकड़ से अधिक की भूमि पर मिट्टी की कटाई की जा चुकी है। जिसकी सूचना मिलने पर वित्त मंत्री श्री किशोर रात करीब 11 बजे रेंगनिया पहुंचे। मंत्री का काफिला देख मौके पर उपस्थित मिट्टी उत्खनन में लगे सभी लोग फरार हो गये। स्थल पर देखा गया की मिट्टी करने वाली मशीन पोकलेन तथा मिट्टी के परिवहन कार्य में लगे तीन ट्रेलर (क्रमशः

बीआर 26 जीसी 5571, सीजी 22 ए 0156, सीजी 15 इजे 4283) को जप्त किया गया। साथी एक पोकलेन को भी जप्त किया गया। वित्त मंत्री ने बताया कि क्षेत्र में लोगों द्वारा अवैध उत्खनन कर बिहार तथा अन्य राज्यों में मिट्टी मोरम की तस्करी की जा रही है। माफियाओं के द्वारा बिना किसी लीज या बिना वैध कागजात के राजस्व की चोरी की जा रही है। मिट्टी चोरी के मना करने पर माफियाओं के द्वारा स्थानीय लोगों को धमकी दी जाती थी। मिट्टी चोरी के इस बड़े खेल में स्थानीय प्रशासन को संज्ञान लेते हुए कार्रवाई करनी चाहिए

थी। हालांकि ग्रामीणों के द्वारा इसकी सूचना अंचल कार्यालय को भी दी गई थी। जिन पर ठोस कार्रवाई करने की आवश्यकता है। मौके पर एसडीपीओ प्रशांत कुमार को सूचित किया गया। सूचना पाकर प्रशांत कुमार स्थल पर पहुंचे व गाड़ियों को जप्त कर थाने की सुपुर्द किया। सीडीपीओ प्रशांत कुमार ने बताया कि फिलहाल खनन विभाग को सूचित किया गया है। जप्त किए गए वाहनों की जानकारी निकाली जा रही है। खान निरीक्षक हर्षेंद्र कुमार गुप्ता ने बताया कि विभाग द्वारा मामला दर्ज कर कार्रवाई की जायेगी।

जंगल में मिला 15 दिनों से लापता महिला का कंकाल, कपड़ों से हुई पहचान, सनसनी

द्रुथ पथ प्रतिनिधि
पलामू : पलामू के पांडू थाना क्षेत्र के ग्राम बसडीहा स्थित जिन पत्थर जंगल के पास एक महिला का कंकाल मिलने से पूरे इलाके में सनसनी फैल गयी है। मृतका की पहचान बसडीहा गांव निवासी विनोद राम की 37 वर्षीय पत्नी सुनीता देवी के रूप में की गयी है। वह पिछले महीने से लापता थी। कंकाल के पास बिखरे कपड़ों को देखकर परिजनों ने उसकी पहचान की। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले की जांच शुरू कर दी है। परिजनों के अनुसार, सुनीता देवी 29 मई को जंगल में लकड़ी चुनने गयी थी। देर शाम तक जब वह घर वापस नहीं लौटी, तो परिजनों ने उसकी काफी खोजबीन की। कोई सुराग न मिलने पर परिजनों ने इस संबंध में पांडू थाने में गुमशुदगी का मामला दर्ज कराया था।

गुरुवार शाम गांव के एक व्यक्ति ने जिन पत्थर जंगल के पास जमीन पर खून के धब्बे और बिखरे हुए कपड़े देखे। उसने तुरंत इसकी सूचना ग्रामीणों को दी। शुक्रवार सुबह जब परिजन और ग्रामीण सामूहिक रूप से घटनास्थल पर पहुंचे, तो वहां एक मानव कंकाल मिला। कंकाल के बगल में पड़े कपड़ों को देखकर परिजनों के होश उड़ गये। उन्होंने कपड़ों से सुनीता देवी की पहचान की। घटना की जानकारी मिलते ही पांडू थाना पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंची। पुलिस ने कंकाल को अपने कब्जे में लेकर छानबीन शुरू कर दी है। महिला की मौत कैसे हुई और उसका कंकाल वहां कैसे पहुंचा, पुलिस इन सभी बिंदुओं पर गहनता से जांच कर रही है। इधर, महिला का कंकाल मिलने की खबर जैसे ही गांव में फैली, मृतका के घर में चीत्कार मच गया और पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गयी है।

द्रुथ पथ प्रतिनिधि
पश्चिमी सिंहभूम : किरिबुरु हिलटॉप स्थित केटीआई कॉन्फ्रेंस रूम में शुक्रवार को एएलसी, सेल प्रबंधन और झारखंड मजदूर संघ (झामसंस) के बीच बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली को लेकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक हुई। यूनियन की ओर से महामंत्री राजेंद्र सिंघिया ने कहा कि वर्ष 1973 से लागू सॉर्टिंग स्टैंडिंग ऑर्डर के तहत धारा 16(बी) व 16(सी) के अनुसार कर्मचारियों की उपस्थिति दर्ज होती रही है और इसमें बायोमेट्रिक प्रणाली का कोई प्रावधान नहीं है। उनका कहना था कि बिना संशोधन के इसे लागू करना नियमों के विरुद्ध है। सेल प्रबंधन की ओर से महाप्रबंधक अमित विश्वास ने मॉडल स्टैंडिंग ऑर्डर का हवाला देते हुए बायोमेट्रिक व्यवस्था लागू करने

का पक्ष रखा। यूनियन ने बताया कि इस मामले को लेकर सीजीआईटी कोर्ट में वाद लंबित है तथा 15 जून को सुनवाई निर्धारित है। साथ ही आईटी एक्ट की धारा 33 का उल्लंघन करते हुए कहा गया कि विवाद विचारार्थ न रहने तक सेवा शर्तों में

बायोमेट्रिक व्यवस्था पर एएलसी, सेल प्रबंधन और झामसंस के बीच वार्ता



का पक्ष रखा। यूनियन ने बताया कि इस मामले को लेकर सीजीआईटी कोर्ट में वाद लंबित है तथा 15 जून को सुनवाई निर्धारित है। साथ ही आईटी एक्ट की धारा 33 का उल्लंघन करते हुए कहा गया कि विवाद विचारार्थ न रहने तक सेवा शर्तों में

सरसोत में अवैध हथियार के साथ युवक गिरफ्तार, दो देशी कट्टा जब्त

द्रुथ पथ प्रतिनिधि
पलामू : जिले के हरिहरगंज थाना क्षेत्र के सरसोत गांव में अवैध हथियार रखने के मामले में पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार कर उसके निशानदेही पर दो देशी कट्टा बरामद किया है। मामले की जानकारी छतरपुर एसडीपीओ प्रशांत कुमार ने शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी। एसडीपीओ ने बताया कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि सरसोत गांव का एक युवक अवैध देशी कट्टा अपने पास रखे हुए है। सूचना के आधार पर पुलिस अशोक पलामू के निर्देश पर एक विशेष छापामारी टीम का गठन किया गया। टीम ने कार्रवाई करते हुए सरसोत गांव निवासी उषेंद्र साव के पुत्र अभय कुमार उर्फ अभय राज उर्फ लड्डू (19 वर्ष) को गिरफ्तार कर लिया। पुछताछ के दौरान युवक की निशानदेही पर दो अलग-अलग स्थानों पर छिपाकर रखे गये दो अवैध देशी कट्टा बरामद किये गये। बरामदगी के बाद पुलिस ने हथियारों को जब्त कर लिया। इस संबंध में हरिहरगंज थाना में कांड संख्या 105/2026 दर्ज किया गया है। मामले में गिरफ्तार युवक एवं एक अज्ञात व्यक्ति के विरुद्ध आर्स एक्ट की धारा 25(1-बी)ए एवं 26 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गयी है। गिरफ्तार आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।

फूड इंस्पेक्टर ने मिठाई दुकान में मारा छापा, जारी किया नोटिस, एकत्र किया नमूना

द्रुथ पथ प्रतिनिधि
साहेबगंज : आम लोगों को बेहतर और गुणवत्ता पूर्ण खाद्य पदार्थ उपलब्ध नहीं कराए जाने वाले दुकानदारों की जांच अब शुरू हो गई है। पाकुड़ के खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी मनोज कुमार जो साहेबगंज जिले के अतिरिक्त प्रभार में हैं। शुक्रवार को उन्होंने साहेबगंज जिले के बरहरवा प्रखंड क्षेत्र के कोटालपोखर बाजार के विभिन्न मिठाई दुकान में छापा मारा और वहां से नमूना कलेक्ट किया

तथा कई दुकानदारों को खाद्य पदार्थ सही नहीं होने पर उन्हें खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के तहत नोटिस थमाया। कुछ दुकानदारों को कड़ी हिदायत देते हुए कहा कि राजा रानी रंग तथा और भी कलरफुल रंग का उपयोग मिठाई तथा नाश्ते के सब्जी और छोले में नहीं करनी है। फूड इंस्पेक्टर मनोज कुमार ने बताया कि हाटपाड़ा, शांतिमोड़, रेलवे फाटक, सहित अन्य जगह पर जांच किया गया है और कड़ी हिदायत भी दिया

गया है तथा कुछ लोगों का सैंपल गीक पाया गया है। जिनकी गड़बड़ी थी उन्हें नोटिस जारी कर जवाब तलब किया गया है। तंतोप जनक जवाब नहीं प्राप्त होने पर जुमाना तथा प्राथमिकी भी दर्ज किए जाने की प्रावधान है। अभी हम लोग पूरी जांच कर रहे हैं। कुछ सैंपल इकट्ठा किया गया है। जांच रिपोर्ट आने के बाद ही आमों की कार्रवाई की जाएगी। उक्त मौके पर काफी संख्या में खाद्य सुरक्षा विभाग कर्मी मौजूद थे।

प्रकार का रंग या कोई भी केमिकल का उपयोग मिठाई या नाश्ते में नहीं करना है। ऐसे दुकानदार अगर करते हुए पकड़े जाएंगे तो उनके विरुद्ध हम लोग पहले नोटिस जारी करेंगे। अगर वह अपने कार्यशैली में सुधार नहीं लाते हैं तो उनके विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करके कार्रवाई भी करते हैं। उन्होंने कहा कि प्राथमिक जांच में कोटालपोखर बाजार के हाटपाड़ा, शांतिमोड़, रेलवे फाटक, सहित अन्य जगह पर जांच किया गया है और कड़ी हिदायत भी दिया

द्रुथ पथ के लिए प्रकाशक एवं मुद्रक कुमार भारती के द्वारा डी.बी. कॉर्प लिमिटेड, भास्कर प्रिंटिंग प्रेस गोविंदपुर मेन रोड, अशोक नगर के.जी. आश्रम, धनबाद (झारखंड) से मुद्रिक एवं नियर भाटिया शिव मंदिर, गांधी नगर धनबाद से प्रकाशित फोन नं. 7004605076, 9852421580

संपादक:- रवि रंजन * इस अंक में प्रकाशित समाचार के चयन एवं सम्पादन हेतु पी आर वी एक्ट की धारा 7 के अंतर्गत उतरदायी। ई. मेल:-truthpath941@gmail.com आर. एन. आई. नंबर . -JHAHIN/2023/90593

सक्षिप्त खबरें

सत प्रतिशत दिव्यांग सलमा खातून को मिला डालसा का सहारा



सरकारी योजनाओं से जोड़ने की पहल तेज ।

समाज के हर वर्ग का उत्थान हो इसके लिए डालसा तत्पर न्यायाधीश ।

दृथ पथ प्रतिनिधि

धनबाद: सरकारी दफ्तरों का चक्कर लगाते थक गई शत प्रतिशत दिव्यांग सलमा खातून को आज डालसा ने जीवन जीने की नई उम्मीद दी है. धनबाद के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण निकेश कुमार सिन्हा के निर्देश पर शत प्रतिशत दिव्यांग सलमा खातून को दिव्यांगता प्रमाण पत्र उपलब्ध करा दिया गया है दिव्यांग प्रमाण पत्र मिलने के बाद सलमा काफी खुश नजर आईं वहीं इस संबंध में जानकारी देते हुए अवर न्यायाधीश सह सचिव डालसा मयंक तुषार टोपनो ने बताया कि सलमा खातून के दिव्यांग होने एवं सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित रहने की सूचना प्राप्त होती है मामले को गंभीरता से लिया गया। क्षेत्र के अधिकार मित्र ओमप्रकाश दास को आवश्यक कार्रवाई का निर्देश दिया गया। उनके प्रयास तथा संबंधित चिकित्सा पदाधिकारी के सहयोग से सलमा खातून का दिव्यांगता प्रमाण पत्र बनवाकर उपलब्ध करा दिया गया। न्यायाधीश ने बताया कि प्रमाण पत्र मिलने के बाद अब उन्हें विभिन्न सरकारी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिलाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है. इसके अतिरिक्त सलमा खातून के तीन बच्चों को भी विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए कार्रवाई शुरू हो गई है.

आंदोलन स्थगित करने का आग्रह



दृथ पथ प्रतिनिधि

धनबाद: एसबीआई ने ठगी के शिकार हुए भुक्तभोगी बासुदेव ठाकुर को आंदोलन स्थगित करने को कहा है। भुक्तभोगी ने उसके जवाब में एसबीआई से कहा कि संदिग्ध व्यक्ति विजय कुमार शकामुरी को 35.5 लाख हस्तांतरण करने से पूर्व हमें कॉल क्यों नहीं किया. एसबीआई ने ठगी के शिकार हुए भुक्तभोगी बासुदेव ठाकुर को आंदोलन स्थगित करने की बात कही है। भुक्तभोगी ने उसके जवाब में एसबीआई से कहा कि संदिग्ध व्यक्ति विजय कुमार शकामुरी को 35.5 लाख हस्तांतरण करने से पूर्व हमें कॉल क्यों नहीं किया पहले इसकी लिखित दे, तत्पश्चात सत्याग्रह वापस लिया जाएगा। सत्याग्रह चौथे दिन भुक्तभोगी बासुदेव ठाकुर ने एसएसपी और डीसी से भेंट कर अपनी पीड़ा और व्यथा सुनाई। विदित हो कि रणधीर वर्मा चौक धनबाद में सपरिवार सत्याग्रह पर बैठे बासुदेव ठाकुर ने एसबीआई के रीजनल प्रबंधक को पत्र देकर अपने खाते से हुई 35.5 लाख निकासी की बिंदुवार जांच करने की मांग की है, साथ ही साथ वरीय पुलिस अधीक्षक और डीसी से भेंट कर कहा कि एसबीआई द्वारा चेक से संदिग्ध व्यक्ति को हस्तांतरण करने से पहले कॉल करने से 35.5 लाख रुपया गबन से बच जाता, जिसके कारण मेरा पूरा परिवार सड़क पर आ गया है। इन्होंने वरीय पुलिस प्रशासन से भी जांच की मांग की है। धनबाद आज चौथे दिन जारी है, ग्राम स्वराज अभियान के जगत महतो ने कहा कि बासुदेव ठाकुर की चेक से निकासी की जांच तुरंत कर दोषी बैंक कर्मी/अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। सत्याग्रह में बासुदेव ठाकुर के साथ उनका पुत्र विनोद ठाकुर, सतेंद्र ठाकुर, उपेंद्र ठाकुर, प्रदीप कुमार, रामजी ठाकुर, नाती रंजन ठाकुर, शिवम कुमार, अभिषेक ठाकुर सहित अन्य लोग दिन रात सत्याग्रह में शामिल होकर जिला प्रशासन और बैंक से गबन की राशि रिकवरी की मांग किया।

जिला मारवाड़ी सम्मेलन का प्रतिभा सम्मान समारोह



दृथ पथ प्रतिनिधि

धनबाद: जिला मारवाड़ी सम्मेलन द्वारा 14 जून रविवार को संध्या 05 बजे से राजकमल सरस्वती विद्या मंदिर, धनसार, धनबाद में प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया जायेगा। इसी आयोजन के संदर्भ में शुक्रवार को अग्रसेन भवन हीरापुर में आयोजित कांफ्रेंस में धनबाद जिला मारवाड़ी सम्मेलन के अध्यक्ष चेतन गोयनका ने बताया कि इस अवसर पर जिले के विभिन्न क्षेत्रों शैक्षणिक, खेल, कला, सांस्कृतिक एवं सामाजिक सेवाओं में उल्लेखनीय उपलब्धि प्राप्त करने वाले बालक- बालिकाओं एवं युवाओं को सम्मानित किया जाएगा। समारोह में समाज के अनेक गणमान्य अतिथियों की उपस्थिति रहेगी प्रिस वार्ता में चेतन गोयनका अध्यक्ष धनबाद जिला मारवाड़ी सम्मेलन, कृष्णा अग्रवाल प्रांतिय उपाध्यक्ष, दीपक रुईया संयोजक समेत धनबाद जिला मारवाड़ी सम्मेलन के अन्य सदस्य मौजूद थे।

बिना लाइसेंस संचालित होटल ट्रायोटेल को निगम ने किया सील

दृथ पथ प्रतिनिधि

धनबाद: नगर निगम ने बिना वैध अनुज्ञप्ति (लाइसेंस) संचालित प्रतिष्ठानों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत सरायढेला स्थित होटल ट्रायोटेल पर कार्रवाई करते हुए उसके संचालन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। साथ ही होटल परिसर को सील करने का आदेश जारी किया गया है। नगर निगम से प्राप्त जानकारी के अनुसार, झारखंड शहरी क्षेत्र धर्मशांला, विवाह भवन, बैंकवेट हॉल, लॉज एवं हॉटेल निर्माण एवं अनुज्ञप्ति नियमावली, 2013 के तहत होटल ट्रायोटेल, लक्ष्मी काम्प्लेक्स, मेन रोड, सरायढेला, वार्ड संख्या-24, धनबाद के संचालक/मालिक भानु खत्री को लाइसेंस प्राप्त करने के लिए सार्वजनिक सूचना एवं नोटिस के माध्यम से पर्याप्त अवसर दिया गया था। इसके बावजूद निर्धारित अवधि के भीतर अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया। निगम अधिकारियों के अनुसार आवश्यक लाइसेंस के बिना प्रतिष्ठान का संचालन नियमों के विपरीत पाया गया। होटल ट्रायोटेल के संचालन पर तत्काल रोक लगाते हुए परिसर को सील करने का आदेश जारी किया गया।

विकास योजनाओं में मिली गड़बड़ी, डीसी ने धनबाद सीओ पर की कार्रवाई, लिपिकों का वेतन रोका



दृथ पथ प्रतिनिधि

धनबाद: उपायुक्त आदित्य रंजन ने शुक्रवार को पुटकी स्थित धनबाद पांडरकनाली एवं पेटिया पंचायत में विभिन्न योजनाओं का औचक निरीक्षण किया गया। टीम ने पंचायतों में अनुआ आवास, प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण), जन वितरण प्रणाली, मनरेगा, आंगनवाड़ी केंद्र, आयुष्मान आरोग्य मंदिर व अन्य योजनाओं का औचक निरीक्षण कर उपायुक्त को अपनी रिपोर्ट सौंपी। रिपोर्ट की समीक्षा करने के क्रम में उपायुक्त ने धनबाद अंचल के अतिरिक्त सरकारी जमीन के अतिक्रमण की भी समीक्षा की। उन्होंने अंचल अधिकारी को अतिक्रमणकारियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया। वहीं सचिव तथा दुबराजडीह के सहायक

अभियंता (ईई) के कार्य को असंतोष पाए जाने पर स्पष्टीकरण देने का निर्देश दिया। वहीं धनबाद अंचल की समीक्षा के क्रम में विभिन्न रजिस्ट्रारों की अनुपलब्धता, विभिन्न पंजी में सही संधारण नहीं करने पर कड़ी नाराजगी जताते हुए उपायुक्त ने धनबाद अंचल के लिपिक एवं सभी कर्मियों का तत्काल प्रभाव से वेतन रोकने का निर्देश दिया। उपायुक्त ने धनबाद अंचल में सरकारी जमीन के अतिक्रमण की भी समीक्षा की। उन्होंने अंचल अधिकारी को अतिक्रमणकारियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया। वहीं धनबाद अंचल की समीक्षा के



दौरान उपायुक्त ने धनबाद अंचल के अंचल अधिकारी को शो-कोज किया। दरअसल, विनोद बिहारी चौक के समीप गैरवादा जमीन पर अवैध कब्जा कर कई दुकानों का निर्माण किया गया है। जिसे लेकर उपायुक्त ने धनबाद सीओ को अतिक्रमण हटाने के आदेश दिए थे। इस कार्य में अपेक्षित प्रगति नहीं होने के कारण उपायुक्त ने कड़ी फटकार लगाते हुए सीओ को शो-कोज करने के निर्देश दिया। साथ में अंचल अधिकारी को एसएनएमएमसीएच के आसपास से अतिक्रमण हटाने तथा जेसी मल्लिक स्थित मल्लिक तालाब को

अतिक्रमण मुक्त करने का भी निर्देश दिया। बैठक के दौरान उपायुक्त ने सभी अंचल अधिकारियों को लैंड बैंक बनाने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि सभी अंचल में लैंड बैंक बन जाने से भारत सरकार एवं राज्य सरकार की योजना के लिए सरकारी जमीन आसानी से उपलब्ध होगी। योजनाएं धरातल पर उतरेंगी। जमीन उपलब्ध नहीं होने के कारण कई महत्वपूर्ण योजना खूट जाती है। लैंड बैंक बनने से योजना के लिए सबसे उपयुक्त स्थल का चयन आसानी से किया जा सकेगा। बैठक में पेयजलापूर्ति, भूमि हस्तांतरण, जल जीवन मिशन, मनरेगा, आवास

निर्माण सहित अन्य योजनाओं की समीक्षा की गई। बैठक में उपायुक्त आदित्य रंजन, उप विकास आयुक्त सन्नी राज, अपर समाहर्ता विनोद कुमार, धनबाद सीओ रामप्रवेश कुमार, पुटकी सीओ विकास आनंद, जिला शिक्षा पदाधिकारी अभिषेक झा, जिला समाज कल्याण पदाधिकारी स्नेह कश्यप, जिला आपूर्ति पदाधिकारी पंकज कुमार, डीसीएलआर दिलीप कुमार महतो, प्रभारी पंचायती राज पदाधिकारी कालिदास मुंडा, पीएचईडी एक एवं दो के कार्यपालक अभियंता के अलावा विभिन्न विभागों के पदाधिकारी मौजूद थे।

पेयजल संकट के समाधान का किया जा रहा है प्रयास: डीसी

दृथ पथ प्रतिनिधि

धनबाद: जिले में पेयजल की समस्या का समाधान का प्रयास किया जा रहा है। धनबाद सदर में भी पेयजल की समस्या है। यहां कि समस्या का भी समाधान किया जा रहा है। कुछ कोलियरी क्षेत्रों में पाइप लाइन और बोरिंग से जलापूर्ति संभव नहीं है। इन क्षेत्रों में टैंकों से पानी की आपूर्ति की जाएगी। उक्त बातें डीसी आदित्य रंजन ने शनिवार को कही। डीसी ने अधिकारियों के साथ पुटकी अंचल सह धनबाद प्रखंड कार्यालय में उच्च स्तरीय बैठक की। इसमें पेयजल संकट से निदान के उपायों पर भी चर्चा हुई। विकास योजनाओं की स्थिति की भी डीसी ने समीक्षा की। बैठक में डीडीसी सन्नी राज भी मौजूद थे। बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत में डीसी ने कहा कि जिले में सबसे ज्यादा जल संकट धनबाद प्रखण्ड में है जिसके समाधान के लिए प्रखण्ड में बैठक कर समस्या को दूर करने पर चर्चा हुई। बीसीसीएल के कोलियरी इलाकों में पानी की सबसे अधिक समस्या है। यहां की समस्या का 100 प्रतिशत समाधान नहीं हो सकता। ऐसे क्षेत्रों में टैंक आदि से पानी की आपूर्ति की जा रही है। उन्होंने कहा कि रेलवे से एनओसी मिलते ही



धनबाद प्रखण्ड कार्यालय के निकट ग्रामीण इलाकों में पाइप लाइन बिछा दी जाएगी। एनओसी मिलने के बाद धनबाद बोकारो सड़क पर पुरिया से प्रखण्ड कार्यालय तक नई एप्रोच सड़क बनेगी। डीएमपीडीआई से सड़क बनेगा। छह महीने से रेलवे के एनओसी के लिए काम रुका हुआ है। उन्होंने बताया कि तीन महीनों में तीन हजार चापाकल, पाइप लाइन, व सोलर व्यवस्था में सुधार किया गया है। अभी भी बड़ी लागत वाली समेत चार से पांच सौ चापाकलों की समस्या को दूर करना बाकि है। जिसको सुधार करने का निर्देश दिया गया है। डीसी ने कहा कि अंचल के अधिकारियों को लैंड बैंक बनाने का

निर्देश दिया गया है। अधिकारियों को निर्देशित किया कि अंचल की सरकारी भूमि को जल्द चिन्हित किया जाय। ताकि केंद्र व राज्य की योजनाओं के लिए जल्द से स्कूल, अस्पताल के लिए उपयोगितापूर्ण जमीन उपलब्ध कराई जा सके। बैठक में पंचायती राज पदाधिकारी काली दास मुंडा, अपरसमाहर्ता विनोद कुमार, समाजिक सुरक्षा के निदेशक नियाज अहमद, समाज कल्याण पदाधिकारी स्नेहलता कश्यप, पुटकी बीडीओ सह सीओ विकास आनंद, सीओ राम प्रवेश कुमार, सीडीपीओ अलका रानी के अलावा जिले के विभिन्न विभागों के अभियंता कर्मी मौजूद थे। उपायुक्त

के निर्देश पर सात टीमों ने धनबाद प्रखण्ड के सात पंचायत नावाडीह, दामोदरपुर, धोखरा, पांडरकनाली, सियाल गुदरी, गोपीनाथडीह व पेटिया पंचायत के स्कूल, आंगनवाड़ी, जनवितरण प्रणाली, सचिवालय भवन के क्रिया कलापो का निरीक्षण किया। सियालगुदरी के ईंदिरा आवास आंगनवाड़ी केंद्र में सेविका नीलिमा कुमारी ने कार्यपालक दंडाधिकारी रविंद्र नाथ ठाकुर का प्रदेश के रीति-रिवाज अनुरूप स्वागत किया। टीम करीब आधे घण्टे तक केंद्र की गतिविधियों का निरीक्षण किया। डीसी ने बताया कि गठित टीम ने सभी पंचायतों का दौरा कर जांच किया कहीं कोई त्रुटि नहीं मिली।

कांग्रेस बचाओ जिला अध्यक्ष हटाओ के नारों के साथ विक्षुब्ध कांग्रेसियों ने कैडल मार्च निकाला



दृथ पथ प्रतिनिधि

धनबाद: जिलाध्यक्ष संतोष सिंह से नाराज विक्षुब्ध कांग्रेसियों ने कैडल मार्च निकालकर जिला अध्यक्ष के प्रति अपनी नाराजगी जताई। कांग्रेस बचाओ जिला अध्यक्ष हटाओ के नारे भी लगे। कांग्रेसी बड़ी संख्या में इसमें शामिल हुए। कांग्रेस नेता राजेश्वर सिंह यादव ने बताया कि अस्तुष्ट कांग्रेसियों के मामले में शीर्ष नेतृत्व के द्वारा गठित दो सदस्यीय जांच टीम धनबाद पहुंची थी। सफिट हाउस में जांच टीम से मुलाकात नहीं होने पर सभी विक्षुब्ध कांग्रेसी गांधी सेवा सदन में घंटों टीम के आने का इन्तजार करते रहे। टीम के नहीं आने पर कैडल मार्च निकालकर अपना आक्रोश व्यक्त किया गया। उन्होंने बताया कि संतोष सिंह के जिला अध्यक्ष पद पर रहने से कांग्रेस पार्टी कमजोर स्थिति में पहुंच गई है। लगातार लोक सभा विधानसभा और मेयर चुनाव में भी कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा। वहीं मनोज सिंह ने कहा कि हम सभी कांग्रेस के सच्चे सिपाही हैं। वर्तमान जिला अध्यक्ष को पद मुक्त कराने तक आंदोलन जारी रखेंगे। मौके पर र-किरंजन सिंह, राजेश्वर सिंह यादव, मनोज सिंह, माधो सिंह, सरजू शर्मा, हुमायूं राजा, बबलू दास, प्रीम रवानी, बैभव सिन्हा, अशोक लाल, रंजेश यादव, माला झा एवं अन्य कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद थे।

कोयला मंत्रालय के उप सचिव ने बीसीसीएल के सीवी एरिया का निरीक्षण किया



दृथ पथ प्रतिनिधि

धनबाद: कोयला मंत्रालय के उप सचिव रॉबिन गांगटे ने बीसीसीएल की कोलियरी का निरीक्षण किया। वे सीवी एरिया चांच यूजी एवं लाईकडीह डीप यूजी माईंस तथा सीएमपीडीआई एक्सप्लोरेशन साइट, लाईकडीह डीप का निरीक्षण किया। यह निरीक्षण टेम्पेरी माइन क्लोजर प्लान (टीएमसीपी) के अंतर्गत संचालित गतिविधियों की समीक्षा के उद्देश्य से किया गया। दौरे के क्रम में सर्वप्रथम सीवी एरिया कार्यालय में टीएमसीपी के अंतर्गत संचालित गतिविधियों की विस्तृत जानकारी प्रस्तुतीकरण के माध्यम से दी गई। इस दौरान माइन क्लोजर से संबंधित



विभिन्न पहलुओं तथा कार्यों की वर्तमान प्रगति एवं आगामी कार्ययोजना के बारे में विस्तार से अवगत कराया गया। साथ ही टीएमसीपी के अंतर्गत किए जा रहे कार्यों की समयबद्धता, गुणवत्ता मानकों तथा निगरानी तंत्र पर भी विस्तृत जानकारी प्रस्तुत की गई इसके उपरान्त टीम द्वारा अमलगमेटेड चांच यूजी एवं लाईकडीह डीप यूजी माईंस का स्थल निरीक्षण कर माइन क्लोजर से संबंधित विभिन्न कार्यों की प्रगति का जायजा लिया गया। निरीक्षण के दौरान टेम्पेरी माइन क्लोजर प्लान के अंतर्गत किए जा रहे कार्यों की समीक्षा की। कहा कि संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया

कि सभी कार्यों को निर्धारित समय-सीमा के भीतर एवं निर्धारित मानकों के अनुरूप पूर्ण किया जाए। दौरे के अंतिम चरण में सीएमपीडीआई एक्सप्लोरेशन साइट, लाईकडीह डीप का निरीक्षण किया गया, जहाँ संचालित अन्वेषण कार्यों का अवलोकन करते हुए भविष्य में खदान संचालन की संभावनाओं एवं संसाधनों के प्रभावी उपयोग पर बल दिया गया। उप सचिव रॉबिन गांगटे ने कार्यों की प्रगति पर संतोष व्यक्त करते हुए माइन क्लोजर से संबंधित गतिविधियों के समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण निष्पादन के निर्देश दिए। इस अवसर पर महाप्रबंधक, सीवी एरिया, संजय कुमार सिंह, टीएमसीपी (पीपी) संजय सिंह, अतिरिक्त महाप्रबंधक शांतनु चक्रवर्ती, ओएसडी, सीसीओ, धनबाद श्री बी. एन. पंडित, एक्टिंग आरडी, आरआई-2 श्री पार्थ दास, बीसीसीएल की एचओडी (पर्यावरण) मारिया अहसान, उप-प्रबंधक (पर्यावरण) आदर्श कुमार, डीबीओसीपी के प्रोजेक्ट ऑफिसर चिरंजीव मुखर्जी, सीएमपीडीआई के एचओडी (पर्यावरण) वैभव कुमार, एरिया मैनेजर (पर्यावरण) प्रदुमन कुमार शाह, एचओडी (भू-विज्ञान), सीएमपीडीआई आरसी अधिकारी, एरिया मैनेजर (ई एंड एम) अशोक कुमार भुनिया तथा एरिया मैनेजर (सिविल) विशाल कुमार सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।

संक्षिप्त खबरें

मुख्य पार्षद ने डीएम से की 200 केवीए ट्रांसफॉर्मर लगाने की मांग
ओवरलोड ट्रांसफॉर्मर बना मुसीबत, बिजली संकट से जूझ रहे रूपीनवासी

लो-वोल्टेज के कारण पानी की मोटर, कूलर और अन्य उपकरण हो रहे प्रभावित

फतेहपुर (गया जी) (एजेंसी) : नगर पंचायत फतेहपुर के स्टेशन रोड स्थित प्रखंड कार्यालय के समीप लगाए गए 100 केवीए विद्युत ट्रांसफॉर्मर पर बढ़ते भार के कारण क्षेत्र के लोगों को लगातार लो-वोल्टेज और बिजली आपूर्ति की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। समस्या की गंभीरता को देखते हुए नगर पंचायत के मुख्य पार्षद रवि कुमार ने जिला पदाधिकारी तथा को पत्र भेजकर ट्रांसफॉर्मर की क्षमता बढ़ाने की मांग की है। मुख्य पार्षद ने अपने पत्र में कहा है कि वर्तमान में लगा 100 केवीए ट्रांसफॉर्मर क्षेत्र की बढ़ती विद्युत आवश्यकता को पूरा करने में सक्षम नहीं रह गया है। अत्यधिक लोड के कारण बिजली का वोल्टेज लगातार कम हो रहा है, जिससे घरों में लगे पानी के मोटर, पंखे, कूलर और अन्य विद्युत उपकरण सुचारु रूप से काम नहीं कर पा रहे हैं। इसका सीधा असर लोगों की दैनिक दिनचर्या और आवश्यक सुविधाओं पर पड़ रहा है। उन्होंने बताया कि गर्मी के इस मौसम में बिजली और पेयजल दोनों की समस्या लोगों के लिए बड़ी परेशानी का कारण बन गई है। कम वोल्टेज के चलते पानी की आपूर्ति भी प्रभावित हो रही है, जिससे स्थानीय निवासियों में नाराजगी बढ़ रही है। जनहित को देखते हुए मुख्य पार्षद ने जिला प्रशासन से अनुरोध किया है कि संबंधित विभाग को आवश्यक निर्देश देकर मौजूदा 100 केवीए ट्रांसफॉर्मर को 200 केवीए ट्रांसफॉर्मर से प्रतिस्थापित कराया जाए। उनका कहना है कि इससे क्षेत्रवासियों को बेहतर वोल्टेज के साथ निर्बाध विद्युत आपूर्ति मिल सकेगी और लंबे समय से चली आ रही समस्या का समाधान होगा।

पुलिस की घेराबंदी देख जंगल की ओर भागे तस्कर, 590 लीटर देसी-विदेशी शराब जब्त
धनछु पुलिया के पास की गई कार्रवाई, चार बाइक पर लदी शराब बरामद



फतेहपुर (गया जी) (एजेंसी) : गुरपा थाना क्षेत्र में अवैध शराब तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। धनछु गांव स्थित पुलिया के समीप से पुलिस ने 590 लीटर देसी एवं विदेशी शराब के साथ चार मोटरसाइकिल जब्त की हैं। हालांकि पुलिस की घेराबंदी देख तस्कर वाहन छोड़कर जंगल का लाभ उठाते हुए फरार हो गए। थानाध्यक्ष शिवनंदन कुमार ने बताया कि क्षेत्र में नियमित गप्त और निगरानी अभियान चलाया जा रहा था। इसी दौरान सूचना मिली कि झारखंड क्षेत्र से शराब की खेप धनछु के रास्ते लाई जा रही है। सूचना मिलते ही पुलिस टीम को मौके पर भेजकर घेराबंदी की गई। पुलिस बल को देखते ही तस्कर शराब लदी बाइक छोड़कर जंगल की ओर भाग निकले। जब्त वाहनों की तलाशी लेने पर करीब 530 लीटर देसी शराब एवं 60 लीटर विदेशी शराब बरामद हुई। कुल 590 लीटर अवैध शराब और तस्करी में प्रयुक्त चार मोटरसाइकिलों को जब्त कर लिया गया है। थानाध्यक्ष ने बताया कि मामले में गुरपा थाना में प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। साथ ही फरार तस्करी की पहचान कर उनकी गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है। पुलिस की इस कार्रवाई से क्षेत्र में शराब तस्करी के बीच हड़कंप मच गया है।

फतेहपुर व टनकुप्पा प्रखंड में 17-18 जून को लगेगा जनकल्याण शिविर
लाभुकी को एक ही छत के नीचे मिलेंगी सरकारी योजनाओं की सुविधाएं

केंद्र व राज्य सरकार की 17 से अधिक कल्याणकारी योजनाओं का होगा लाभ वितरण व ऑन-द-स्पॉट निबटारा

फतेहपुर (गया जी) (एजेंसी) : केंद्र एवं राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ अंतिम पात्र व्यक्ति तक पहुंचाने के उद्देश्य से फतेहपुर और टनकुप्पा प्रखंडों में 17 एवं 18 जून को दो दिवसीय प्रखंड सहयोग-सह-जन-कल्याण शिविर आयोजित किया जाएगा। शिविर में आम लोगों को एक ही स्थान पर विभिन्न सरकारी योजनाओं से संबंधित सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। इस संबंध में जिला पदाधिकारियों द्वारा आदेश जारी कर अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए हैं। फतेहपुर बीडीओ शशिभूषण साहू और टनकुप्पा बीडीओ अलीशा कुमारी ने बताया कि शिविर का उद्देश्य केंद्र एवं राज्य सरकार की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ अंतिम पात्र व्यक्ति तक सुनिश्चित रूप से पहुंचाना है। शिविर में आयुष्मान भारत योजना, 70 वर्ष से अधिक आयु के लोगों के लिए आयुष्मान वय वंदना कार्ड, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, किसान क्रेडिट कार्ड, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, मुख्यमंत्री कन्या उद्यान योजना, मुख्यमंत्री उद्यमी योजना, ग्राम परिवहन योजना, स्वयं सहायता भत्ता योजना सहित 17 से अधिक योजनाओं से जुड़े आवेदन, निबंधन, ई-केवाईसी, सत्यापन एवं लाभ वितरण का कार्य किया जाएगा। अधिकारियों ने बताया कि शिविर में प्रत्येक योजना के लिए अलग काउंटर और नोडल पदाधिकारी की व्यवस्था रहेगी। लाभार्थियों के मार्गदर्शन के लिए हेल्प डेस्क तथा स्वास्थ्य जांच के लिए मेडिकल स्टैंट भी लगाए जाएंगे। इसके लिए जिला प्रशासन की ओर से व्यापक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित करने तथा आवश्यक दस्तावेजों के साथ लाभार्थियों की अधिकतम भागीदारी सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है। उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य है कि पात्र लाभार्थियों को योजनाओं का लाभ समय पर मिले और विभिन्न विभागों की सेवाएं एक ही स्थान पर उपलब्ध कराई जा सकें।

वेतन नहीं मिलने से एमबीए विभाग के कर्मचारी बेहाल
भागलपुर, (एजेंसी) : तिलकमांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के एमबीए विभाग में कार्यरत टीचिंग और नॉन-टीचिंग स्टाफ पिछले 10 महीनों से मानदेय नहीं मिलने के कारण गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं। कर्मचारियों का कहना है कि निर्धारित आय बंद होने से परिवार चलाना मुश्किल हो गया है और बच्चों की पढ़ाई तक प्रभावित हो रही है। विभाग के फैकल्टी सदस्य डॉ. पंकज कुमार, डॉ. हार्शिता कुमार, ब्यूटी कुमारी, डॉ. काजी कमरान तथा कर्मचारी डॉ. आशीष कुमार और पंकज चौधरी ने बताया कि कई बार मानदेय भुगतान की मांग उठाने के बावजूद अब तक कोई ठोस समाधान नहीं निकला है। उनका कहना है कि वे भुखमरी जैसी स्थिति का सामना कर रहे हैं और परिवार आर्थिक तंगी से गुजर रहा है। कर्मचारियों के अनुसार, जब वे अपनी समस्या लेकर विभागीय निदेशक के पास जाते हैं तो उन्हें विश्वविद्यालय प्रशासन से संपर्क करने की सलाह दी जाती है। वहीं विश्वविद्यालय प्रशासन ने मामले में सकारात्मक पहल का आश्वासन दिया है। बताया जा रहा है कि एमबीए विभाग की आय-व्यय, मानदेय भुगतान और सेवा अवधि विस्तार को लेकर गठित जांच समिति ने फरवरी में ही अपनी रिपोर्ट प्रभारी कुलपति को सौंप दी थी।

बिहार पंचायत चुनाव 2026: पहली बार सभी पदों पर ईवीएम से होगा मतदान, 21 जून को जारी हो सकता है अंतिम गजट

पटना, (एजेंसी) : बिहार में प्रस्तावित त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2026 की तैयारियां अंतिम चरण में पहुंच गई हैं। राज्य निर्वाचन आयोग और प्रशासनिक विभाग चुनावी प्रक्रिया को समवर्द्ध तरीके से पूरा करने में जुटे हैं। चूँकि पंचायत चुनाव को ग्रामीण लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व माना जाता है। ऐसे में आयोग को कोशिश है कि हर मतदाता बिना किसी दबाव और भय के अपने मताधिकार का प्रयोग कर सके। इस बार पंचायत चुनाव की सबसे बड़ी खासियत यह होगी कि राज्य के सभी पंचायत पदों पर पहली बार पूरी तरह इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) के जरिए मतदान कराया जाएगा। इसके साथ ही बिहार उन चुनिंदा राज्यों में शामिल हो जाएगा, जहां पंचायत स्तर तक चुनाव प्रक्रिया को डिजिटल और अधिक पारदर्शी बनाया जा रहा है। राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार, चुनाव की तैयारियों के तहत सीटों के आरक्षण, परिसीमन और मतदान केंद्रों के पुनर्गठन का कार्य तेजी से चल रहा है। सभी जिलों के प्रशासनिक अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए गए हैं ताकि चुनाव से जुड़ी प्रक्रियाएं तय समय सीमा के भीतर पूरी की जा सकें।



सुझाव जमा कर सकेंगे। प्रशासन का कहना है कि प्राप्त सभी दावों और आपत्तियों को निष्पक्ष जांच की जाएगी। इसके बाद आवश्यक संशोधन कर अंतिम सूची तैयार की जाएगी। आयोग की ओर से 21 जून 2026 को पंचायत चुनाव से संबंधित अंतिम गजट प्रकाशित किए जाने की संभावना है। अंतिम गजट जारी होने के बाद चुनाव कार्यक्रम घोषित करने की प्रक्रिया शुरू होगी।

बहुद्रा गांव में कृषि चौपाल में किसानों को मिली आधुनिक खेती करने की जानकारी

कम लागत में अधिक उत्पादन के बताए गए तकनीकी उपाय

मृदा जांच, किसान आईडी कार्ड और प्राकृतिक खेती के लाभों पर विशेषज्ञों ने डाला प्रकाश



प्राथमिक विद्यालय परिसर में कृषि जन कल्याण चौपाल-सह-खेत बचाओ अभियान 2026 का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में किसानों ने भाग लेकर खेती-किसानी से जुड़ी विभिन्न योजनाओं एवं तकनीकों की जानकारी प्राप्त की।

और उनके समाधान के संबंध में आवश्यक सुझाव दिए। साथ ही किसानों को सरकार द्वारा संचालित विभिन्न कृषि योजनाओं की जानकारी देते हुए उनका लाभ उठाने के लिए प्रेरित किया गया। मौके पर कृषि विशेषज्ञों ने कहा कि वैज्ञानिक पद्धति से खेती अपनाकर किसान कम लागत में बेहतर उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही मृदा परीक्षण के आधार पर उर्वरकों का प्रयोग करने से भूमि की उर्वरता बनी रहती है और फसल की गुणवत्ता में भी सुधार होता है। चौपाल के माध्यम से किसानों को आधुनिक एवं प्राकृतिक खेती के प्रति जागरूक करने के साथ-साथ कृषि क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने का संदेश भी दिया गया।

बीते एक दशक में देश और बिहार दोनों ने विकास का नया अध्याय लिखा है : मुख्यमंत्री

पटना, (एजेंसी) : भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) प्रदेश कार्यालय में शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरे होने के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री स्मार्त चौधरी ने कहा कि बीते एक दशक में देश और बिहार दोनों ने विकास का नया अध्याय लिखा है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने जनसंघ काल से जो भी संकल्प देश के सामने रखा, उसे पूरा किया गया है। उन्होंने कहा कि जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 और 35ए को हटाना तथा अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण जैसी ऐतिहासिक उपलब्धियां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूरी हुई हैं। मुख्यमंत्री ने दावा किया कि वर्ष 2004-05 से 2013-14 के दौरान बिहार को कर मद्द में लगभग 2.80 लाख करोड़ रुपये प्राप्त हुए थे, जबकि पिछले 11-12 वर्षों में यह राशि बढ़कर लगभग 12.90 लाख करोड़ रुपये हो गई है। उन्होंने कहा कि जीएसटी और केंद्र सरकार की नीतियों से राज्य की वित्तीय स्थिति मजबूत हुई है और विकास को नई गति मिली है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज बिहार देश के अग्रणी राज्यों में शामिल है, जहां गांव-गांव तक बिजली पहुंच चुकी है और ग्रामीण सड़क संपर्क में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। राज्य में ग्रामीण सड़कों की लंबाई लगभग 1.20 लाख किलोमीटर तक पहुंच चुकी है और 100 से अधिक आबादी वाले सभी टोलों को पक्की सड़क से जोड़ने का कार्य जारी है। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना का उल्लेख करते हुए कहा कि देशभर में 50 लाख घरों तक सौर ऊर्जा पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है, जिससे लोगों को सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा उपलब्ध हो रही है।

महादलित परिवार की बेटी ममता बनीं पैरामेडिकल प्रवेश परीक्षा में टॉपर

अनुसूचित जाति वर्ग में हासिल किया प्रथम स्थान, सामान्य वर्ग में भी आठवां रैंक प्राप्त कर बढ़ाया क्षेत्र का मान



शिक्षक चंदन कुमार ने आठ वर्षों तक निःशुल्क पढ़ाकर दिया सपनों को आकार

पैरामेडिकल प्रवेश परीक्षा में अनुसूचित जाति (एससी) वर्ग में टॉप कर एक नया इतिहास रच दिया है। इतना ही नहीं, उसने सामान्य वर्ग की मेरिट सूची में भी आठवां रैंक हासिल कर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है। ममता के पिता सुरेंद्र मांझी बेहत साधारण और एक गरीब व आर्थिक रूप से कमजोर परिवार से आते हैं। सीमित संसाधनों और कठिन परिस्थितियों के बावजूद ममता ने अपनी पढ़ाई जारी रखी और सफलता का नया अध्याय लिखा। परिवार की आर्थिक स्थिति बेहद चलकर होने के कारण पढ़ाई के दौरान उसे कई तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। कई बार संसाधनों की कमी उसके सपनों के आड़े आई, लेकिन उसने हार नहीं मानी। सीमित साधनों और संघर्षों के बीच लगातार मेहनत करती रही और अंततः सफलता का वह मुकाम हासिल कर लिया, जो आज हजारों युवाओं के लिए प्रेरणा बन गयी है। ममता के पिता सुरेंद्र मांझी और माता रेशमी देवी मजदूरी कर परिवार का भरण-पोषण करते हैं। विपरीत परिस्थितियों के बावजूद उन्होंने बेटी की शिक्षा में कोई कमी नहीं आने दी। इसी का परिणाम है कि ममता ने इस वर्ष मैट्रिक परीक्षा में 435 अंक प्राप्त कर प्रथम श्रेणी से सफलता हासिल की और आगे की पढ़ाई जारी रखी। गोर्खनिया गांव से बांढिलबांधा तक प्रतिदिन करीब तीन किलोमीटर पैदल चलकर कोचिंग पहुंचने वाली ममता का लक्ष्य मेडिकल क्षेत्र में उत्कृष्ट सेवा देना है। उनकी सफलता से परिवार, गांव, मित्रों और शुभचिंतकों में उत्साह का आँसू आई, लेकिन उसने हार नहीं मानी। सीमित साधनों और संघर्षों के बीच लगातार मेहनत करती रही और

गया जिला परिवहन विभाग ने राजस्व वसूली में वित्तीय वर्ष 2025-26 में बनाया नया कीर्तिमान

परिवहन विभाग ने निर्धारित लक्ष्य से डेढ़ गुना राजस्व संग्रह, राज्य स्तर पर मिली सराहना



उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए अधिकारियों और कर्मियों को किया गया सम्मानित

गया जी (एजेंसी) :जिला परिवहन विभाग ने वित्तीय वर्ष 2025-26 में राजस्व संग्रह और कर वसूली के क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल करते हुए नया कीर्तिमान स्थापित किया है। विभाग ने निर्धारित लक्ष्य की तुलना में शत-प्रतिशत से कहीं अधिक करीब डेढ़ सौ फीसदी राजस्व अर्जित कर राज्य स्तर पर अपनी अलग पहचान बनाई है। बेहतर प्रवर्तन (इंफॉर्मेटिव) कार्यों और राजस्व वृद्धि में उत्कृष्ट योगदान के लिए विभागीय अधिकारियों एवं कर्मियों को सम्मानित भी किया गया है। विभागीय आंकड़ों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए जिला परिवहन कार्यालय को 2097 लाख रुपये राजस्व संग्रह का लक्ष्य दिया गया था। इसके विरुद्ध विभाग ने करीब 3926 लाख रुपये से अधिक की राजस्व प्राप्ति कर लगभग डेढ़ सौ प्रतिशत लक्ष्य हासिल किया। यह राशि वाहन कर, परमिट शुल्क तथा यातायात नियमों के उल्लंघन से जुड़े मामलों में लगाए गए ई-चालान के माध्यम से प्राप्त हुई है। डीटीओ राजेश कुमार के नेतृत्व में विभाग ने राजस्व वसूली के निर्धारित लक्ष्यों को समय से पहले पूरा करते हुए राज्य के राजस्व संग्रह में महत्वपूर्ण योगदान दिया। विभाग को इस उपलब्धि को बिहार में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले जिलों में गया जिला को पांचवें स्थान में शामिल किया गया है। ओवरलॉडिंग और बिना टैक्स वाले वाहनों पर चला अभियान विभाग के अधिकारियों ने बताया कि इस सफलता के पीछे डिजिटल और पारदर्शी कार्यप्रणाली की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। वाहन और सारथी पोर्टल के माध्यम से

अनलाइन सेवाओं को सुचारु रूप से संचालित किया गया जिससे कर भुगतान और विभिन्न परिवहन सेवाओं में आसानी हुई। इसके साथ ही ओवरलॉडिंग करने वाले तथा बिना कर भुगतान के सड़क पर चलने वाले वाहनों के खिलाफ लगातार सख्त प्रवर्तन अभियान चलाया गया। उत्कृष्ट कार्य निष्पादन और राजस्व वृद्धि में अहम योगदान देने के लिए मोटर वाहन निरीक्षक (एमबीआई) सुनील कुमार, अथर प्रवर्तन निरीक्षक राजीव कुमार तथा अशोक कुमार पासवान को विभाग की ओर से सम्मानित किया गया। डीटीओ राजेश कुमार ने इसे टीम वर्क का परिणाम बताया है। भविष्य में भी इसी तरह बेहतर प्रदर्शन जारी रखने का संकल्प व्यक्त किया। समीक्षा बैठक में उत्कृष्ट कार्य

चान्हो पश्चिमी क्षेत्र के विभिन्न गांवों का दौरा, ग्रामीणों की समस्याएं सुनीं



चान्हो। चान्हो प्रखंड के पश्चिमी क्षेत्र के विभिन्न गांवों का जिला परिषद आदिल अजीम ने दौरा कर स्थानीय लोगों की समस्याओं को सुना। तथा उनके शीघ्र समाधान का आश्वासन दिया गया। इस दौरान ग्रामीणों ने क्षेत्र में विकास कार्यों से जुड़ी कई समस्याओं से अवगत कराया। दौरे के क्रम में ग्रामीणों ने पररा्यत पंचायत भवन के मरम्मत कार्य में अनियमितता की शिकायत की। शिकायत मिलने के बाद जिला परिषद आदिल अजीम ने पंचायत भवन का निरीक्षण किया, जहां निर्माण कार्य में कई त्रुटियां पाई गईं। मामले को गंभीरता से लेते हुए इसके जानकारी जिला आयुक्त एवं जूनियर इंजीनियर को दी गई। इसके बाद संबंधित ठेकेदार को तत्काल कार्य बंद करने का निर्देश दिया गया और जांच पूरी होने तक मरम्मत कार्य स्थगित रखने को कहा गया। हालांकि, ग्रामीणों द्वारा पुनः शिकायत की गई कि ठेकेदार अपनी कमियों को छिपाने के लिए जांच से पहले ही निर्माण कार्य करवा रहा है। इस संबंध में संबंधित अधिकारियों को अवगत कराते हुए ठेकेदार के विरुद्ध उचित कार्रवाई की मांग की गई है। बताया गया कि पंचायत भवन मरम्मत कार्य की लागत 24 लाख 92 हजार 100 रुपये है। ग्रामीणों का कहना है कि हाल ही में मुखिया निधि से भी पंचायत भवन की मरम्मत कराई गई थी। ऐसे में सरकारी राशि का दुरुपयोग न हो तथा निर्माण कार्य की गुणवत्ता सुनिश्चित की जाए। ग्रामीणों ने प्रशासन से पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों पर कार्रवाई करने की मांग की है। ग्रामीणों की सभी समस्याओं को हल करने की बात जिला परिषद आदिल अजीम ने किया। आदिल अजीम ने इस से संबंधित ठेकेदार, इंजीनियर आदि को गुणवत्ता का ध्यान रखने का निर्देश दिया। जिला परिषद आदिल अजीम ने कहा कि हम किसी भी हाल में अपने क्षेत्र में अनियमितता बर्दाश्त नहीं करेंगे।

संपादकीय

जेन-जी महंगाई और बेरोजगारी से परेशान, सपनों में जी रहा

पूरी दुनिया में जेन-जी की आबादी चिंता का कारण बनती चली जा रही है। यह युवा आबादी ना तो अपने परिवार के बारे में सोचती है, नाही समाज के बारे में सोचती है, यह केवल अपने बारे में सोचती है। इसके पास शिक्षा की डिग्रियां भी हैं, लेकिन डिग्री के अनुरूप ज्ञान नहीं है। जीवन जीने का कोई अनुभव नहीं है। वह कोई चीज सीखना भी नहीं चाहते हैं। किसी चीज से जुड़ते हैं और उसे जल्दी ही छोड़ देते हैं। उनका सबसे ज्यादा समय सोशल मीडिया और इंटरनेट पर बीत रहा है, जिसके कारण वह सामान्य ज्ञान से भी दूर होते चले जा रहे हैं। वर्तमान की जो युवा पीढ़ी है वह डिग्री लेकर बड़े-बड़े सपने देखती है लेकिन डिग्री के अनुरूप उसके पास ना तो कोई ज्ञान होता है नाही वह कोई काम करना चाहता है जिसके कारण यह युवा पीढ़ी एक बड़ी चिंता का कारण भी बन रही है। जेन-जी को ना तो वामपंथी विचारधारा पर विश्वास है ना ही उसे पूंजीवाद पर विश्वास है, वह पूरी तरह से सेलिफ़िश होकर केवल अपने बारे में सोचती है। उसे अपने परिवार और मां-बाप की कठिनाइयों से भी कोई सरोकार नहीं रहता है। वह जब भी बात करता है केवल अपने हित की बात करता है। वह अपने माता-पिता और परिवार से दूर रहकर केवल अपनी जरूरतों को ध्यान में रखते हुए अपने परिवार से उतना ही जुड़ता है जो उसकी जरूरत पूरी करने के लिए जरूरी होती है। भारत, अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, जर्मनी, यूरोपीय देश सभी में जेन-जी के इस बर्ताव से सामाजिक और पारिवारिक व्यवस्था में अब एक तनाव देखने को मिल रहा है। हाल ही में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के इंस्टीट्यूट आफ पॉलिटिक्स ने 2020 से 2025 के बीच जो सर्वे किया था उसमें यह बात खुलकर सामने आई कि इस युवा पीढ़ी को पूंजीवाद वामपंथ समाजवाद इत्यादि विचारधारा से कोई लेना-देना नहीं है। यह केवल अपनी जरूरत से जुड़कर ही अपनी बात रखता है। मेरा किराया कम करो, फीस माफ़ करो, मुक्त बस सेवा दो, मुझे नौकरी दो, नौकरी भी सबसे अच्छी वाली चाहिए है, जिसमें बड़ा वेतन मिलता हो, कॉरपोरेट ऑफिस हो। इस तरह की मांग इस युवा पीढ़ी की होती है, लेकिन यह अनुभव प्राप्त करने के लिए अथवा जो भी नौकरी या रोजगार करना चाहता है जो उसके सपने में है उसके लिए वह अपने आपको तैयार भी नहीं कर रहा है। सोशल मीडिया के जरिए उसके सपने बड़े-बड़े हो गए हैं। सारी दुनिया में क्या हो रहा है यह उसे पता है लेकिन उसका करियर कैसे बनेगा इसके बारे में वह जरा भी गंभीर नहीं है।

हमें भूत के बारे में पछतावा नहीं करना चाहिए, ना ही भविष्य के बारे में चिंतित होना चाहिए, विवेकवान व्यक्ति हमेशा वर्तमान में जीते है।

: चाणक्य

हम सभी एक दुसरे की मदद करना चाहते है, मनुष्य ऐसे ही होते है, हम एक दुसरे के सुख के लिए जीना चाहते है दु:ख के लिए नहीं।

: चार्ली चेपलिन

सूडोकु नवताल- 7541					* * * * *				
					मध्यम				
4	6		3	8	9		7		
			9	6	5	4			
				8					
4	5		4	6	8				
2				1	7				1
			3						
5	9		7	2	6				
7	6		4	3	9	2			

- सूडोकु नवताल -7540 का हल**
- प्रत्येक पंक्ति में 1 से 9 तक के अंक भरे जाने आवश्यक हैं।
 - प्रत्येक आड़ी और खड़ी पंक्ति में एवं 3×3 के वर्ग में किसी भी अंक की पुनरावृत्ति न हो इसका विशेष ध्यान रखें।
 - पहले से मौजूद अंकों को आप हटा नहीं सकते।
 - पहेली का केवल एक ही हल है।

दैनिक पंचांग	
13 जून 2026 को सूर्योदय के समय की ग्रह स्थिति	शनिवार 2026 वर्ष का 164 वा दिन दिशाशुल पूर्व ऋतु ग्रीष्म। विक्रम संवत् 2083 शक संवत् 1948 मास ज्येष्ठ पक्ष कृष्ण तिथि त्रयोदशी 16.08 बजे को समाप्त। नक्षत्र कृत्तिका 01.17 बजे रात्र को समाप्त। योग सुकर्मा 17.29 बजे को समाप्त। करण गर 05.56 बजे, वणिज 16.08 बजे तदनंतर विधि 02.16 बजे रात्र को समाप्त। चन्द्रायु 24.2 घण्टे रवि क्रांति उत्तर 23° 12' सूर्य उल्लसण कालि अहरण 1872739 जूलियन दिन 2461204.5 कालिगुण संवत् 5128 कल्पारंभ संवत् 1972949128 सृष्टि प्रहारांभ संवत् 1955885128 वीरनिर्वाण संवत् 2552 हिजरी सन् 1447 महोना जिल्हेज तारीख 27 विशेष मासिक शिवरात्रि।
ग्रह स्थिति	लनारंभ समय
सूर्य बुध में 07.23 बजे तक	मिथुन 05.27 बजे से
चंद्र बुध में 07.40 बजे से	कर्क 07.40 बजे से
मंगल मेष में 09.57 बजे से	सिंह 09.57 बजे से
बुध मिथुन में 12.09 बजे से	कन्या 12.09 बजे से
गुरु कर्क में 14.19 बजे से	तुला 14.19 बजे से
शुक्र मीन में 16.34 बजे से	वृषिक 16.34 बजे से
शनि कर्क में 18.50 बजे से	धनु 18.50 बजे से
राहु कुंभ में 20.55 बजे से	मकर 20.55 बजे से
केतु सिंह में 22.42 बजे से	कुंभ 22.42 बजे से
राहुकाल 9.00 से 10.30 बजे तक	मीन 00.14 बजे से मेष 01.45 बजे से वृष 03.25 बजे से
दिन का चौघड़िया	रात का चौघड़िया
शुभ 05.55 से 07.23 बजे तक	लाभ 05.37 से 07.10 बजे तक
काल 07.23 से 08.51 बजे तक	उद्वेग 07.10 से 08.42 बजे तक
रोग 08.51 से 10.19 बजे तक	शुभ 08.42 से 10.14 बजे तक
उद्वेग 10.19 से 11.46 बजे तक	अमृत 10.14 से 11.47 बजे तक
चर 11.46 से 01.14 बजे तक	चर 11.47 से 01.19 बजे तक
लाभ 01.14 से 02.42 बजे तक	रोग 01.19 से 02.51 बजे तक
अमृत 02.42 से 04.10 बजे तक	काल 02.51 से 04.23 बजे तक
काल 04.10 से 05.37 बजे तक	लाभ 04.23 से 05.56 बजे तक
चौघड़िया शुभरात्रि - शुभत्व श्रेष्ठ शुभ, अमृत व लाभ, मध्यम चर, अशुभ उद्वेग, रोग व काल। सभी समय भारतीय मानक समय की वरत। बिन्दु के आधार पर है अत: आप अपने स्थानीय समयनुसार ही देखें।	© Jgrajugadika.com, Bangalore

फिर सुलग रही खाड़ी: होर्मुज जलडमरूमध्य बंद, दुनियाँ में हड़कंप

ईरान ने होर्मुज जलडमरूमध्य बंद से ऊर्जा सुरक्षा, वैश्विक व्यापार मुद्रास्फीति और आर्थिक स्थिरता को लेकर नई चिंताएं पैदा कर दी हैं।

होर्मुज जलडमरूमध्य बंद से केवल क्षेत्रीय नहीं वैश्विक अर्थव्यवस्था को झटका की संभावना?, इस जलमार्ग में व्यवधान का असर सीधे अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा बाजारों पर दिखाई देता है।

वैश्विक स्तरपर पश्चिम एशिया एक बार फिर वैश्विक भू-राजनीतिक उथल-पुथल का केंद्र बन गया है। 11 जून 2026 को स्थिति तब और गंभीर हो गई जब ईरान ने अमेरिका के साथ बढ़ते सैन्य टकराव के बीच दुनियाँ के सबसे महत्वपूर्ण ऊर्जा मार्गों में से एक, होर्मुज जलडमरूमध्य, को सभी वाणिज्यिक जहाजों और तेल टैंकरों के लिए बंद करने की घोषणा कर दी। ईरान ने यह बंद करने की घोषणा कर दी है कि जलडमरूमध्य से गुजरती की कोशिश करने वाले किसी भी जहाज को निशाना बनाया जाएगा। यह कदम कथित रूप से अमेरिका और ईरान के बीच समुद्री टकराव तथा अमेरिकी सैन्य कार्रवाइयों के बाद उठाया गया है। इसके साथ ही वैश्विक ऊर्जा बाजारों में भारी बेचैनी फैल गई है। ब्रेंट क्रूड की कीमत लगभग 95.40 डॉलर प्रति बैरल और अमेरिकी डब्ल्यूटीआई लगभग 92.6 डॉलर प्रतिबैरल तक पहुंच गया है। दुनियाँ की लगभग 20 प्रतिशत तेल और गैस आपूर्ति इसी मार्ग से गुजरती है, इसलिए इस घटनाक्रम ने ऊर्जा सुरक्षा, वैश्विक व्यापार, मुद्रास्फीति और आर्थिक स्थिरता को लेकर नई चिंताएं पैदा कर दी हैं। संयुक्त राष्ट्र में भारत ने भी खाड़ी क्षेत्र में व्यापारिक जहाजों पर बढ़ते हमलों और भारतीय नागरिकों की सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंता व्यक्त की है। वर्तमान घटनाक्रम केवल क्षेत्रीय संघर्ष नहीं बल्कि वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए एक बड़े झटके के रूप में देखा जा रहा है।

मैं एडवोकेट किशन सनमुखदास भावनानी गोंदिया महाराष्ट्र यह कह रहे हैं कि यह विकुल सही है। ऊर्जा आयात पर बढ़ती लागत अंततः उपभोक्ताओं तक धुरी माना जाता है। फारस की खाड़ी

को अरब सागर से जोड़ने वाला यह संकरा समुद्री मार्ग सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, कुवैत, कतर, इराक और ईरान जैसे प्रमुख ऊर्जा उत्पाक देशों के निर्यात का मुख्य रास्ता है। सामान्य परिस्थितियों में प्रतिदिन करोड़ों बैरल तेल और विशाल मात्रा में एलएनजी इसी मार्ग से दुनिया के विभिन्न हिस्सों तक पहुंचती है। यही कारण है कि जब भी इस जलमार्ग में व्यवधान आता है, उसका असर सीधे अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा बाजारों पर दिखाई देता है। वर्तमान संकट में भी निवेशकों और ऊर्जा कंपनियों ने आपूर्ति बाधित होने की आशंका को देखते हुए तेल खरीदना शुरू कर दिया, जिसके परिणामस्वरूप कच्चे तेल की कीमतों में तत्काल उछाल देखने को मिला।

साथियों, अंतरराष्ट्रीय बाजारों की पहली प्रतिक्रिया बंद कीमतों में तेजी के रूप में सामने आई है। ब्रेंट क्रूड लगभग 95 डॉलर प्रति बैरल के स्तर तक पहुंच गया है जबकि डब्ल्यूटीआई भी 92 डॉलर प्रति बैरल के आसपास कारोबार कर रहा है। ऊर्जा विश्लेषकों का मानना है कि यदि जलडमरूमध्य लंबे समय तक बंद रहता है या सैन्य संघर्ष और बढ़ता है तो तेल की कीमतें 100 डॉलर प्रति बैरल से ऊपर भी जा सकती हैं। वैश्विक वित्तीय बाजारों में भी अस्थिरता बढ़ने की आशंका है क्योंकि ऊर्जा लागत लगभग हर आर्थिक गतिविधि को प्रभावित करती है।

साथियों, भारत के लिए यह संकट विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि देश अपनी आवश्यकता का 80 प्रतिशत से अधिक कच्चा तेल आयात करता है। भारत की ऊर्जा जरूरतों का बड़ा हिस्सा खाड़ी क्षेत्र से पूरा होता है और उसका एक बड़ा भाग होर्मुज जलडमरूमध्य के रास्ते आता है। इसलिए इस मार्ग में किसी भी प्रकार की रुकावट का सीधा असर भारतीय ऊर्जा सुरक्षा पर पड़ता है। यदि तेल की आपूर्ति प्रभावित होती है तो भारत का आयात बिल बढ़ेगा, चालू खाता घाटा बढ़ सकता है और रुपये पर दबाव पड़ सकता है। ऊर्जा आयात पर बढ़ती लागत अंततः उपभोक्ताओं तक पहुंचती है और महंगाई को बढ़ावा देता

है। सबसे पहला प्रभाव पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर दिखाई दे सकता है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चा तेल महंगा होने से भारतीय तेल विपणन कंपनियों की लागत बढ़ जाती है। यदि मौजूदा तनाव कुछ और दिनों या सप्ताहों तक बना रहता है तो पेट्रोल और डीजल की खुदरा कीमतों में उल्लेखनीय वृद्धि की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। विशेषज्ञों का अनुमान है कि लंबी अवधि तक ऊंचे तेल मूल्य बने रहने पर ईंधन की कीमतों में कई रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी हो सकती है। इसका सीधा असर आम नागरिकों, किसानों, उद्योगों और परिवहन क्षेत्र पर पड़ेगा। पेट्रोल और डीजल केवल वाहन चलााने का साधन नहीं हैं बल्कि पूरी अर्थव्यवस्था की जीवरेखा हैं। डीजल की कीमत बढ़ने का अर्थ है कि ट्रकों, बसों और मालवाहक वाहनों की परिचालन लागत बढ़ जाएगी। जब परिवहन महंगा होता है तो फल, सब्जियां, दूध, अनाज, दवाइयाँ और अन्य आवश्यक वस्तुओं की कीमतें भी बढ़ने लगती हैं। तही कारण है कि तेल कीमतों में वृद्धि को अक्सर हममहंगाई की जननी कहा जाता है। एक बार यदि ईंधन लागत बढ़ती है तो उसका असर अर्थव्यवस्था के लगभग हर क्षेत्र में सटीकता से दिखाई देता है।

साथियों, 7 जून 2026 से मृग लग गया है व खेती के कार्य शुरू हो चुके हैं, कृषि क्षेत्र भी इस संकट से अछूता नहीं रहेगा। भारत में सिंचाई, कृषि मशीनों और खाद्य आपूर्ति श्रृंखला का बड़ा हिस्सा डीजल पर निर्भर है। डीजल महंगा होने से किसानों की लागत बढ़ेगी और इसका असर खाद्यान्न कीमतों पर पड़ सकता है। इसके अलावा उर्वरक उद्योग प्राकृतिक गैस और पेट्रोकेमिकल उत्पादों पर निर्भर है। यदि ऊर्जा लागत बढ़ती है तो उर्वरकों का उत्पादन भी महंगा हो सकता है। विमानन क्षेत्र पर भी दबाव बढ़ सकता है। विमान ईंधन की लागत एयरलाइंस के कुल खर्च का बड़ा हिस्सा होती है। यदि अंतरराष्ट्रीय तेल कीमतें लगातार ऊंची बनी रहती हैं तो घरेलू और अंतरराष्ट्रीय हवाई किराए में

नामांकन निरस्तीकरण की अस्पष्टता और लोकतंत्र की चुनौती

क्या चुनाव लड़ने का अधिकार प्रशासनिक विवेक पर निर्भर हो सकता है? भारतीय लोकतंत्र की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यहाँ अंतिम निर्णय जनता के हाथ में होता है। जनता अपने प्रतिनिधियों को चुनती है, सरकारें बनाती है और उन्हें बदलती भी है। किंतु लोकतांत्रिक प्रक्रिया का यह मूल सिद्धांत तब प्रश्नों के घेरे में आ जाता है जब किसी उम्मीदवार को चुनाव लड़ने से पहले ही नामांकन निरस्त कर प्रक्रिया से बाहर कर दिया जाता है। हाल के वर्षों में नामांकन पत्रों और शपथपत्रों (फार्म 26) से जुड़े विवादों ने एक महत्वपूर्ण संवैधानिक प्रश्न खड़ा किया है—क्या चुनाव लड़ने का अधिकार स्पष्ट कानूनी मानकों से संचालित हो रहा है, या फिर यह अधिकारियों की व्याख्या और विवेक पर निर्भर होता जा रहा है? यह प्रश्न किसी एक दल या व्यक्ति का नहीं है। यह भारतीय लोकतंत्र की निष्पक्षता और विश्वसनीयता से जुड़ा प्रश्न है।

जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 36 नामांकन पत्रों की जांच की प्रक्रिया निर्धारित

करती है। इस धारा का मूल उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि केवल वही उम्मीदवार चुनाव लड़ें जो कानूनी द्वारा निर्धारित योग्यता रखते हों और जिनके नामांकन में कोई गंभीर कानूनी दोष न हो। साथ ही यह धारा स्पष्ट रूप से यह भी संकेत देती है कि तकनीकी या मामूली त्रुटियों के आधार पर उम्मीदवार को चुनाव लड़ने से वंचित नहीं किया जाना चाहिए। लोकतंत्र की भावना यही कहती है कि जहाँ संदेह हो, वहाँ निर्णय चुनाव के पक्ष में होना चाहिए, न कि बहिष्कार के पक्ष में। यही कारण है कि न्यायालयों ने समय-समय पर रिटनिंग आफोसर की भूमिका को सीमित बताया है। रिटनिंग आफोसर कोई न्यायालय नहीं है और न ही वह विस्तृत तथ्यात्मक जांच करने वाली एजेंसी है। उसका कार्य प्रारंभिक परीक्षण करना है, न कि जटिल कानूनी विवादों का अंतिम निपटारा करना।

शपथपत्र और मतदाता का अधिकार

सर्वोच्च न्यायालय ने एडीआर तथा बाद के अनेक निर्णयों में मतदाता के जानने के अधिकार को लोकतंत्र

में समान रूप से लागू हो। *लोकतंत्र के लिए वास्तविक खतरा* बहस का केंद्र किसी विशेष उम्मीदवार का भाग्य नहीं होना चाहिए। वास्तविक चिंता इससे कहीं बड़ी है। यदि अपूर्ण खुलासा, अपर्याप्त जानकारी और सारभूत दोष की स्पष्ट परिभाषा नहीं होगी, तो भविष्य में कोई भी उम्मीदवार विवादों और व्याख्याओं के आधार पर चुनाव लड़ने से रोका जा सकता है। लोकतंत्र में चुनाव लड़ने का अधिकार केवल उम्मीदवार का व्यक्तिगत अधिकार नहीं है। यह मतदाताओं का भी अधिकार है कि वे अधिकतम विकल्पों में से अपना प्रतिनिधि चुन सकें। जब किसी उम्मीदवार का नामांकन निरस्त किया जाता है, तब केवल एक व्यक्ति प्रक्रिया से बाहर नहीं होता बल्कि मतदाताओं के सामने उपलब्ध एक विकल्प भी समाप्त हो जाता है। इसलिए नामांकन निरस्तीकरण की शक्ति को अत्यंत सावधानी से प्रयोग किया जाना चाहिए। क्या झूठी जानकारी को अनदेखा किया जाए? इस तर्क का यह अर्थ

फीफा विश्व कप: जहाँ आँसू भी एक भाषा बन जाते हैं और खुशी भी

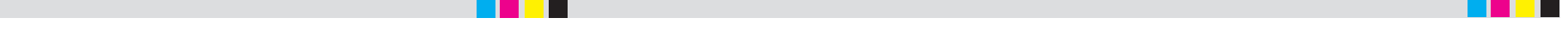
कभी-कभी एक सीटी, एक गोल और एक मैदान पूरी दुनिया को एक परिवार बना देते हैं। 11 जून 2026 को एक स्ट्राइक्यो एजेंडे का मंच बन गया। 2026 का विश्व कप अपने विस्तार और समावेशिता से अलग पहचान बना रहा है। 48 टीमों और 12 समूहों के नए प्रारूप में शीर्ष दो के साथ आठ सर्वश्रेष्ठ तीसरे स्थान वाली टीमों को भी नॉकआउट का अवसर मिला है। यही बन गया। तीन देशों की संयुक्त मेजबानी, 48 टीमों की अभूतपूर्व भागीदारी, 104 मुकामलों और 39 दिनों का यह महाउत्सव खेल से आगे बढ़कर मानवता का साझा उत्सव बन चुका है। यहाँ हर गोल केवल जाल नहीं हिलाता, बल्कि सरहदों के पार दिलों को भी जोड़ता है। फुटबॉल एक बार फिर साबित कर रहा है कि दुनिया को जीतने की सबसे बड़ी ताकत हथियारों में नहीं, सपनों और भावनाओं में बसती है।

विश्व कप का इतिहास उन आंखों की कहानी है जिनमें अंधंभय सपने पलते हैं। 1930 में उरुग्वे से शुरू हुई यह यात्रा 2022 में मेक्सिको के स्वर्णिम

से बड़ा होता है। न्यूयॉर्क-न्यू जर्सी के मेटलाइफ़ स्टीडियम में फाइनल पहली बार सुपर बाउल शैली के भव्य हाफ्टाइम शो के साथ और भी बढ़ावा बनेगा। यह महाआयोजन खेल और वैश्विक संस्कृति के संगम से जन्मी स-झेदारी, आस्था और उम्मीद की गाथा है, जो विभाजन की छाया में डूबी दुनिया में उजाले की किरण बनकर उभरता है।

जब खेल मैदान विज्ञान की प्रयोगशाला में बदल जाता है, तब फुटबॉल केवल मुकामलों नहीं, भविष्य का अनुभव बन जाता है। अर्थ-स्वच्छालित ऑफसाइड तकनीक, खिलाड़ियों के डिजिटल 3-डी अवतार, एआई आधारित विश्लेषण, कनेक्टेड बॉल और हाफ्टाइम इंटरव्यू जैसे व्यवस्थाएं खेल अनुभव को नई ऊंचाइयों पर ले जा रही हैं। चार पैरालो वाली ट्रिब्यूनल गेंद ने ऊंचाई वाले मैदानों में नई उड़ान और रोमांच पैदा किया है। अब दर्शक सिर्फ खेल नहीं देखते, बल्कि रियल-टाइम डेटा और विश्लेषण के साथ उसे गहराई से महसूस करते हैं। यह रूप दिखाता है कि परंपरा और

नवाचार विरोधी नहीं, बल्कि एक-दूसरे के पूरक हैं—जहाँ खिलाड़ी वर्तमान हैं और तकनीक भविष्य की आहट। इस विश्व कप की असली ताकत उसका विस्तार नहीं, बल्कि उसकी समावेशिता है। अफ्रीका, एशिया और ओशनिया को अधिक प्रतिनिधित्व मिला है, जिससे यह प्रतियोगिता सचमुच वैश्विक रूप लेती है। नॉर्वे की 28 वर्षों बाद वापसी, स्कॉटलैंड और ऑस्ट्रेलिया का लंबे इंतजार का अंत तथा नए देशों का अगमन इसे और जीवंत बनाते हैं। मेजबान देशों के लाखों युवा विश्व स्तरिय खिलाड़ियों को देखकर प्रेरित हो रहे हैं। किसी युवा का पहला विश्व कप गोल व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं, बल्कि पूरे राष्ट्र के सपनों का उत्सव बन जाता है। यही कारण है कि फुटबॉल राष्ट्रवाद से ऊपर उठकर मानवीय एकता का प्रतीक बना है—एक ऐसा पुल जो भाषा, संस्कृति और सीमाओं को दूरियाँ मिटा देता है। निश्चित रूप से इस विराट आयोजन के समक्ष अनेक चुनौतियाँ भी उपस्थित हैं। तीन देशों के बीच लंबी यात्राएं, अलग-अलग समय क्षेत्र, मौसम का



संक्षिप्त समाचार

नेपाल में प्रचंड और बाबूराम भट्टराई के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का परमादेश जारी

काठमांडू। पूर्व बाल सैनिकों से संबंधित मामले में नेपाल के उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को परमादेश जारी किया, जिससे देश के दो पूर्व प्रधानमंत्रियों और माओवादी नेताओं के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का रास्ता साफ हो गया है। माओवादी सशस्त्र सेना में रहे लेनिन बिष्ट और अन्य की ओर से दायर इस याचिका में पूर्व प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल 'प्रचंड' और डॉ. बाबूराम भट्टराई को भी प्रतिवादी बनाया गया था। उच्चतम न्यायालय ने याचिकाकर्ताओं के पक्ष में फैसला सुनाते हुए रिट याचिका में उठाई गई मांगों के अनुरूप परमादेश जारी किया। लंबे समय से चल रहे इस कानूनी मामले में न्यायालय का यह फैसला एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम माना जा रहा है। इस फैसले को नेपाल के सशस्त्र संघर्ष के दौरान बाल सैनिकों को भर्ती से जुड़े आरोपों पर आगे कानूनी प्रक्रिया का मार्ग प्रशस्त करने वाले कदम के रूप में देखा जा रहा है। हालांकि, इसके वास्तविक कानूनी प्रभावों का निर्धारण न्यायालय के पूर्ण फैसले की सामग्री सामने आने के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा। फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए लेनिन बिष्ट ने न्याय और पूर्व बाल सैनिकों की एकता के अभियान में सहयोग करने वाले सभी लोगों के प्रति आभार व्यक्त किया। मोशल मीडिया पर एक पोस्ट में बिष्ट ने कहा, "पूर्व बाल सैनिकों के लिए न्याय और एकता की लड़ाई में योगदान देने वाले सभी लोगों को बधाई। आज हमने एक बड़ी लड़ाई जीत ली है। उच्चतम न्यायालय की पूर्ण पीठ ने परमादेश जारी किया है। आप सभी का एक बार फिर धन्यवाद।" उच्चतम न्यायालय ने अभी फैसले का पूर्ण पाठ सार्वजनिक नहीं किया है, जिसकी प्रतीक्षा है।

मप्र के कुनों में चीतों की निगरानी के लिए तैनात जर्मन शेफर्ड डॉग की मौत

श्रयोपुर। मध्य प्रदेश के श्रयोपुर जिले में स्थित प्रसिद्ध कुनों राष्ट्रीय उद्यान में चीतों की निगरानी और ट्रेकिंग के लिए तैनात विशेष रूप से प्रशिक्षित जर्मन शेफर्ड डॉग की मौत हो गई है। कुनों के डीएफओ और डिप्टी डायरेक्टर आर. थिरुकुल ने शुक्रवार को इसकी पुष्टि की। उन्होंने बताया कि कुनों का यह जर्मन शेफर्ड कोई साधारण डॉग नहीं था। जंगल में चीतों की हकत पर नजर रखने में वन विभाग की मदद करना उसकी जिम्मेदारी थी। डॉग का काम चीतों की ट्रेकिंग, गरत के साथ वन अमले की सहायता करना था। बुधवार की शाम को कुनों में ट्रेकिंग डॉग की मौत हुई है। मौत के स्पष्ट कारण अभी सामने नहीं आए हैं, लेकिन चीता प्रबंधन की टीम द्वारा प्रारंभिक तौर पर हार्टअटैक को मृत्यु का कारण मान रहे हैं, जबकि स्थानीय स्तर पर डॉग के किसी वाहन की चपेट में आने से मौत होने की बात कही जा रही है। कुनों में डॉग की देखरेख के लिए दो हैडलर तैनात थे। ऐसे में उसकी मौत पर सवाल उठ रहे हैं। कुनों के डिप्टी डायरेक्टर आर. थिरुकुल का कहना है कि डॉग की मौत के बाद गुरुवार को उसका पोस्टमार्टम कराया गया है। प्रारंभिक जांच में हार्ट अटैक की संभावना बताई जा रही है। उसकी मौत की अमली कजह क्या है, यह पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही पता चल सकेगा।



चुनावी भाषण को लेकर कोलकाता के हेयर स्ट्रीट थाने में ममता बनर्जी के खिलाफ एफआईआर

कोलकाता। पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री व तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी के खिलाफ चुनाव प्रचार के दौरान दिए गए एक विवादास्पद बयान को लेकर राजधानी कोलकाता के हेयर स्ट्रीट थाने में प्राथमिकी (एफआईआर) दर्ज की गई है। पुलिस ने लिखित शिकायत के आधार पर भारतीय न्याय संहिता (बोनापस) की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस के अनुसार, विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान ममता बनर्जी ने एक विशेष समुदाय को लेकर टिप्पणी की थी। अपने भाषण में उन्होंने कहा था कि यदि एक समुदाय एकजुट हो जाए तो वह विरोधियों की 'बाहर बजा सकता है'। साथ ही उन्होंने लोगों से भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के खिलाफ भी भड़काया था। इस बयान को लेकर उस समय भी राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया था। इसके पूर्व इस संबंध में नेताजी सूभाषचंद्र बोस रोड निवासी तुषारकांत दास ने 20 मई को नेताजीनगर थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में उन्होंने ममता बनर्जी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की थी। उनका आरोप था कि भले ही किसी समुदाय का नाम सीधे तौर पर नहीं लिया गया हो, लेकिन इस प्रकार की टिप्पणी सांप्रदायिक सौहार्द को प्रभावित कर सकती है और विभिन्न समुदायों के बीच तनाव पैदा कर सकती है। शिकायतकर्ता ने यह भी दावा किया है कि कोलकाता और आसपास के क्षेत्रों में चुनाव के बाद हुई हिंसा और सांप्रदायिक तनाव के लिए इस प्रकार के बयान जिम्मेदार हो सकते हैं। इसी शिकायत के आधार पर हेयर स्ट्रीट थाने में मामला दर्ज किया है। एफआईआर में आरोप लगाया गया है कि पूर्व मुख्यमंत्री की टिप्पणी प्रथम दृष्टया उकसाने वाली, भड़काऊ और सांप्रदायिक प्रकृति की प्रतीत होती है। शिकायत में कहा गया है कि इस तरह के बयान से भय, घृणा और गलतफहमी का माहौल बन सकता है तथा विभिन्न समुदायों के बीच शांति और सौहार्द प्रभावित हो सकता है। शिकायतकर्ता का कहना है कि यदि इस प्रकार की टिप्पणियों को गंभीरता से नहीं लिया गया तो इससे राज्य में सांप्रदायिक सद्भाव और लोकतांत्रिक जागरण को नुकसान पहुंच सकता है। शिकायत में यह भी आरोप लगाया गया है कि चुनाव के दौरान दिया गया यह बयान आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन भी हो सकता है। शिकायतकर्ता ने मामले की निष्पक्ष, पारदर्शी और स्वतंत्र जांच की मांग की है। फिलहाल, पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। मामले में आगे की कार्रवाई जांच के निष्कर्षों के आधार पर की जाएगी।



छत्तीसगढ़ के कांकेर में आकाशीय बिजली गिरने से उपसरपंच सहित तीन की मौत, पांच घायल

कांकेर। छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले के अंतागढ़ ब्लॉक में आज शुक्रवार सुबह आकाशीय बिजली गिरने से एक उप-सरपंच सहित तीन लोगों की मौत हो गई जबकि पांच लोग घायल हो गए हैं। घायलों में एक महिला की हालत गंभीर बताई जा रही है। कांकेर जिले के अंतागढ़ ब्लॉक अंतर्गत ग्राम कलागांव में आज सुबह मनरेगा में काम करने के दौरान हुई बारिश से बचने के लिए ग्रामीण पेड़ के नीचे आ गए थे। इसी दौरान आकाशीय बिजली गिरने से एक उप-सरपंच सहित तीन लोगों की मौत हो गई और पांच लोग घायल हो गए हैं। घायलों में एक महिला की हालत गंभीर बताई जा रही है। मृतकों में संतोष पटेल, प्रकाश पटेल, मनराज पटेल (उपसरपंच) सभी कलागांव के निवासी हैं। सभी के शव को पोस्टमार्टम लिए भेज दिया गया है। अंतागढ़ पुलिस के अनुसार ग्राम कलागांव में मनरेगा के तहत तालाब गहरी करण का कार्य किया जा रहा था। सभी ग्रामीण काम में लगे हुए थे। यहां पर करीब 70 ग्रामीण काम कर रहे थे। इस दौरान अचानक मौसम बदला और तेज आंधी के साथ बारिश होने लगी, बारिश से बचने के लिए सभी मजदूर पास के पेड़ के नीचे आ गये। तभी आकाशीय बिजली गिरी, जिसकी चपेट में आठ लोग आ गए। इसमें तीन पुरुषों की मौत हो गई और पांच महिला गंभीर रूप से घायल हो गईं। सभी को तत्काल इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अंतागढ़ में भर्ती कराया गया। एक महिला को जिसकी हालत गंभीर है, उसे इलाज के लिये कांकेर रेफर किया गया है।



मोदी सरकार के 12 वर्ष विकसित भारत की मजबूत नींव के स्वर्णिम वर्ष

एजेंसी, शिमला। केंद्रीय स्वास्थ्य, परिवार कल्याण, रसायन एवं उर्वरक मंत्री तथा भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 12 वर्ष देश के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज किए जायेंगे। उन्होंने कहा कि यह अवधि केवल एक सरकार का कार्यकाल नहीं, बल्कि विकसित भारत की मजबूत आधारशिला रखने वाले परिवर्तनकारी वर्षों का प्रतीक है। भाजपा द्वारा आयोजित "12 साल विश्वास के, विकास के, जनकल्याण के" अभियान के तहत शुक्रवार को शिमला में आयोजित बुद्धिजीवी सम्मेलन को संबोधित करते हुए नड्डा ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने राजनीति की दिशा और संस्कृति दोनों को बदला है। उन्होंने कहा कि पहले राजनीति जातिवाद, परिवारवाद, तुष्टिकरण और भ्रष्टाचार तक सीमित थी, लेकिन मोदी सरकार ने राजनीति को सेवा, सुशासन और जवाबदेही का माध्यम बनाया है। नड्डा ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश ने कई ऐतिहासिक निर्णय देखे हैं। जम्मू-कश्मीर से धारा 370 हटाना, अयोध्या में श्रीराम मंदिर का निर्माण, मुस्लिम महिलाओं को तीन तलाक से मुक्ति दिलाना और नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) लागू करना ऐसे फैसले हैं, जिन्होंने देश की दिशा और दशा बदलने का कार्य किया है। उन्होंने कहा कि विकास और जनकल्याण की नीतियों के कारण भाजपा को लगातार तीसरी बार जनता का समर्थन मिला है। देश के अधिकांश नागरिक आज भाजपा और एनडीए शासित राज्यों में निवास कर रहे हैं, जो सरकार की नीतियों पर जनता के विश्वास को दर्शाता है। हिमाचल प्रदेश का उल्लेख करते हुए नड्डा ने कहा कि केंद्र सरकार ने प्रदेश को विकास की नई गति प्रदान की है। विलासपुर में एमएस की स्थापना, चंबा, हमीरपुर और नाहन में मेडिकल कॉलेजों का निर्माण तथा राष्ट्रीय राजमार्गों और सड़क परियोजनाओं के विस्तार से प्रदेश की तस्वीर बदली है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत हिमाचल में 14,400 किलोमीटर से अधिक ग्रामीण सड़क नेटवर्क विकसित किया गया है। उन्होंने कहा कि जल जीवन मिशन के तहत हिमाचल में सभी घरों तक पेयजल सुविधा पहुंचाई गई है। उच्चला योजना के माध्यम से लगभग डेढ़ लाख परिवारों को गैस कनेक्शन मिले हैं, जबकि प्रधानमंत्री आवास योजना से एक लाख से अधिक परिवार लाभान्वित हुए हैं।



रंगदारी नहीं देने पर व्यापारी के घर पहुंचे बदमाश, दी जान से मारने की धमकी



एजेंसी, बिजनाोर। उत्तर प्रदेश के बिजनाोर शहर के एक बड़े व्यापारी को कुछ बदमाशों ने जान से मारने की धमकी देकर रुपये देने की मांग की है। पीड़ित व्यापारी ने पुलिस को जानकारी देते हुए मुश्का और कार्यवाही की मांग की है। बृहस्पतिवार की रात्रि को व्यापारी विनीत अग्रवाल उर्फ लालू निवासी नई बस्ती के घर पर दो पहिया वाहन से आये चार युवकों ने फोन करके बाहर आने व रुपये नहीं देने पर मारने की बात कही। गली में शोर मचाया सुनकर आसपास के कई लोग भी बाहर आ गये तो चारों युवक व्यापारी को मारने की धमकी देते हुए भाग गये। व्यापारी विनीत अग्रवाल ने 112 डायल पर फोन कर पुलिस को घटनाक्रम की जानकारी दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने व्यापारी के बयान दर्ज किए हैं। व्यापारी ने पुलिस क्षेत्राधिकारी को इस मामले को लिखित शिकायत करते हुए कहा है कि सत्यम चौधरी, अजुन कर्णवाल, गोलू सहित चार युवक मेरे घर आकर जान से मारने की धमकी देते हुए रुपये की मांग कर रहे थे। रुपय न देने पर मारने की धमकी देकर गए हैं। उन्होंने इन बदमाशों के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की है। थाना बिजनाोर शहर कोतवाली प्रभारी अमर सिंह राठौड़ ने बताया की पुलिस क्षेत्राधिकारी को व्यापारी विनीत द्वारा दी गई तहरीर पर रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है तथा मामले की जांच की जा रही है।

भारत आज दुनिया की सबसे तेज़ी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है : शुभेंदु अधिकारी

एजेंसी, कोलकाता। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि एक समय आधारभूत संरचना विकास के मामले में पिछड़ेने वाला भारत आज दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है। उन्होंने इस बदलाव का श्रेय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) सरकार के पिछले 12 वर्षों के कार्यकाल को दिया। केंद्र में एनडीए सरकार के 12 वर्ष पूरे होने के अवसर पर शुक्रवार को आयोजित संवादादाता सम्मेलन में मुख्यमंत्री ने देश में हुए आर्थिक और आधारभूत संरचना विकास का विस्तृत ब्यौरा प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा कि पिछले 12 वर्षों में देशभर में 1317 नए और आधुनिकीकृत रेलवे स्टेशन विकसित किए गए हैं। इसके अलावा देश के विभिन्न हिस्सों में 164 से अधिक वंदे भारत ट्रेनें संचालित हो रही हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि एक समय राजधानी एक्सप्रेस और शताब्दी एक्सप्रेस ने देश में हुए आर्थिक और पहचान थीं, लेकिन आज वंदे भारत ट्रेनें नए भारत की आकांक्षाओं का प्रतीक बन चुकी हैं। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में देश के एक छोर से दूसरे छोर तक की दूरी और यात्रा का समय कम हुआ है, जिससे आर्थिक गतिविधियों की गति भी तेज हुई है। नागरिक उड्डयन क्षेत्र में हुई प्रगति का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2014 में देश में 74 हवाई अड्डे थे, जबकि आज उनकी संख्या दोगुने से भी अधिक हो चुकी है। उन्होंने दावा किया कि पिछले 12 वर्षों में देश में 90 से अधिक नए हवाई अड्डों का निर्माण किया गया है। सड़क और परिवहन क्षेत्र का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इस अवधि में लगभग चार लाख किलोमीटर सड़कों का निर्माण हुआ है। राष्ट्रीय राजमार्गों का विस्तार किया गया है तथा सीमावर्ती और दूरदराज के क्षेत्रों में संपर्क व्यवस्था को मजबूत किया गया है। उन्होंने कहा कि इन विकास कार्यों ने देश का आर्थिक संरचना को सकारात्मक रूप से बदल दिया है। विकास अब केवल महानगरों तक सीमित नहीं है, बल्कि गांवों और दूरस्थ क्षेत्रों तक भी पहुंच चुका है। पश्चिम बंगाल के संदर्भ में मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में नई सरकार के गठन के माए एक महीने के भीतर केंद्र और राज्य सरकार के बीच बेहतर समन्वय के कारण विकास कार्यों में तेजी आई है। उन्होंने कहा कि केंद्रीय मंत्री लगातार पश्चिम बंगाल का दौरा कर रहे हैं और राज्य सरकार के प्रतिनिधि भी नियमित रूप से दिल्ली जा रहे हैं। इससे विभिन्न परियोजनाओं की स्वीकृति और क्रियान्वयन की प्रक्रिया तेज हुई है। मुख्यमंत्री ने यह भी पुष्टि की कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी हम महीने के अंत में दो दिवसीय पश्चिम बंगाल टूर पर आएंगे। उन्होंने बताया कि 20 जून को पहलें बार मनाए जाने वाले 'बंगाल स्थापना दिवस' के अवसर पर प्रधानमंत्री हुवाली जिले के तारकेश्वर में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। इस दौरान वह राज्य के लिए कई विकास परियोजनाओं की घोषणा भी कर सकते हैं।



छत्तीसगढ़ में निवेश के लिए बिछा रेड कारपेट 9,580 करोड़ रुपये के मिले प्रस्ताव

एजेंसी, रायपुर। छत्तीसगढ़ में निवेश आकर्षित करने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। हैदराबाद में आयोजित 'छत्तीसगढ़ इन्वेस्टर कनेक्ट' कार्यक्रम में विभिन्न क्षेत्रों की सत प्रमुख कंपनियों ने 9,580 करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव दिए हैं, जिससे 7,800 से अधिक रोजगार सृजित होने की संभावना है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने देश के प्रमुख उद्योगपतियों और निवेशकों को छत्तीसगढ़ में निवेश के लिए आमंत्रित करते हुए कहा कि विकसित भारत के ग्रोथ इंजन के रूप में छत्तीसगढ़ तेजी से उभर रहा है और राज्य में निवेशकों के लिए 'रेड कारपेट' बिछा हुआ है। कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री लखन लाल देवांगन सहित दक्षिण भारत के कई बड़े उद्योगपति, निवेशक और कारोबारी प्रतिनिधि मौजूद रहे। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री साय ने बताया कि नई औद्योगिक नीति लागू होने के बाद दिल्ली, मुंबई, बंगलुरु के साथ-साथ जापान और दक्षिण कोरिया में आयोजित इन्वेस्टर कनेक्ट कार्यक्रमों के माध्यम से राज्य को 8 लाख करोड़ रुपये से अधिक के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। राज्य सरकार इन प्रस्तावों को धरालत पर उतारने के लिए तेजी से कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ आज निवेश के लिए देश के सबसे बेहतर राज्यों में से एक बनकर उभर रहा है। राज्य में उद्योगों के लिए आसान प्रक्रियाएं, सिंगल विंडो व्यवस्था, बेहतर बुनियादी सुविधाएं और उद्योग अनुकूल नीतियां उपलब्ध हैं। उन्होंने निवेशकों को छत्तीसगढ़ में उद्योग स्थापित करने का आमंत्रण दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि हैदराबाद ने आईटी, फार्मा, बायोटेक्नोलॉजी और एयरोस्पेस जैसे क्षेत्रों में उल्लेखनीय सफलता हासिल की है। छत्तीसगढ़ भी इन क्षेत्रों में तेजी से आगे बढ़ रहा है और दोनों राज्यों के उद्योगपति एवं उद्यमी मिलकर नए अवसरों का लाभ उठा सकते हैं। उन्होंने कहा कि मध्य भारत में स्थित छत्तीसगढ़ देश का सबसे उपयुक्त लॉजिस्टिक हब बनने की क्षमता रखता है। छत्तीसगढ़ सात राज्यों से घिरा हुआ है और 60 करोड़ से अधिक उपभोक्ताओं तक सीधी पहुंच प्रदान करता है। एयरोस्पेस जैसे क्षेत्रों में उल्लेखनीय सफलता हासिल की है। छत्तीसगढ़ भी इन क्षेत्रों में तेजी से आगे बढ़ रहा है और दोनों राज्यों के उद्योगपति एवं उद्यमी मिलकर नए अवसरों का लाभ उठा सकते हैं। उन्होंने कहा कि मध्य भारत में स्थित छत्तीसगढ़ देश का सबसे उपयुक्त लॉजिस्टिक हब बनने की क्षमता रखता है। छत्तीसगढ़ सात राज्यों से घिरा हुआ है और 60 करोड़ से अधिक उपभोक्ताओं तक सीधी पहुंच प्रदान करता है।



अपराध की जड़ है संस्कारों की कमी: कुमार रणविजय सिंह

एजेंसी, मुरादाबाद। संवेदना केलफेयर सोसाइटी मुरादाबाद द्वारा आयोजित 10 दिवसीय संस्कार शिविर का समापन समारोह शुक्रवार को रंगारंग संस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ हुआ। समारोह में मुख्य अतिथि पुलिस अधीक्षक नगर कुमार रणविजय सिंह ने कहा कि एक पुलिस अधिकारी के रूप में मैं रोज देखा हूँ कि अपराध की जड़ संस्कारों की कमी से है। यदि हम बचपन से ही बच्चों को सही-गलत का भेद, अनुशासन और नैतिकता सिखा दें, तो समाज स्वतः सुरक्षित हो जाएगा। पुलिस अधीक्षक नगर ने आगे कहा कि संवेदना केलफेयर सोसाइटी का यह संस्कार शिविर समाज निर्माण की दिशा में एक सराहनीय कदम है साथ ही मैं इन बच्चों में कल का अनुशासित और जिम्मेदार भारत देख रहा हूँ। विद्यालय की निर्देशिका मेजर डा. मीनू मेहरोत्रा ने कहा कि संस्कार शिविर केवल दस दिन का आयोजन नहीं, बल्कि जीवन भर का पूंजी है। विशिष्ट अतिथि के रूप में कर्मयोगी विद्यापीठ अहमदाबाद से आए स्वामी कृष्णदेव झा ने कहा कि मां बच्चे की पहली गुरु है और उसके लिए संस्कार जीवन की नींव बनाते हैं। विशिष्ट अतिथि प्रताप सिंह गार्स इंटर कॉलेज की प्रधानाचार्या सीमा शर्मा ने रामचरितमानस के आदर्शों का जीवन में उतारने पर जोर दिया।



दो दिवसीय दौरे पर उत्तराखंड पहुंची राष्ट्रपति मुर्मू

एजेंसी, देहरादून। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू दो दिवसीय दौरे पर शुक्रवार को उत्तराखंड पहुंच गईं। जैलीग्रांट एयरपोर्ट पर राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, कैबिनेट मंत्री मुदन कौशिक, मुख्य सचिव आनंद बर्दान, पुलिस महानिदेशक दीपम सेठ ने पुष्पगुच्छ भेंट कर स्वागत किया। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार, राष्ट्रपति आज देहरादून स्थित राष्ट्रपति निकेतन का दौरा करेंगीं। यहां वे राष्ट्रपति आशियाना परिसर में 132 एकड़ के विशाल क्षेत्रफल में विकसित किए जा रहे अत्याधुनिक राष्ट्रपति उद्यान के निर्माण और विकास कार्यों का अवलोकन करेंगीं। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार, राष्ट्रपति आज देहरादून स्थित राष्ट्रपति निकेतन का दौरा करेंगीं। यहां वे राष्ट्रपति आशियाना परिसर में 132 एकड़ के विशाल क्षेत्रफल में विकसित किए जा रहे अत्याधुनिक राष्ट्रपति उद्यान के निर्माण और विकास कार्यों का अवलोकन करेंगीं। राष्ट्रपति परेड की समीक्षा करेंगीं और नवप्रशिक्षित कैडेटों को सलामी देंगीं। राष्ट्रपति के उत्तराखंड दौरे को देखते हुए देहरादून में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है व यातायात और ड्रोन प्रतिबंध संबंधी व्यवस्थाएं लागू की गई हैं।



मेट्टूर बांध से नहीं छोड़ा गया पानी, कावेरी डेल्टा के 16 लाख एकड़ कृषि क्षेत्र पर संकट, किसान निराश

एजेंसी, सेलम। तमिलनाडु के कावेरी डेल्टा क्षेत्र के लाखों किसानों को शुक्रवार को उस समय निराशा का सामना करना पड़ा, जब निर्धारित तिथि 12 जून को मेट्टूर बांध से कुरुवई (प्रारंभिक धान) फसल की सिंचाई के लिए पानी नहीं छोड़ा गया। बांध में जलस्तर और जल भंडारण अपेक्षित स्तर से कम होने के कारण इस वर्ष भी सिंचाई सत्र की शुरुआत समय पर नहीं हो सकी। मेट्टूर बांध कावेरी डेल्टा के 12 जिलों की लगभग 16.05 लाख एकड़ कृषि भूमि के लिए जीवनरेखा माना जाता है। परंपरा के अनुसार हर वर्ष 12 जून से 28 जनवरी तक डेल्टा क्षेत्र में सिंचाई के लिए बांध से पानी छोड़ा जाता है। इसके लिए बांध का जलस्तर कम से कम 90 फीट और जल प्रवाह पर्याप्त होना आवश्यक माना जाता है, ताकि कुरुवई धान की खेती समय पर शुरू हो सके। हालांकि इस वर्ष 12 जून को मेट्टूर बांध का जलस्तर केवल 79.62 फीट दर्ज किया गया, जबकि जल प्रवाह महज 424 क्यूसेक रहा। जल भंडारण और आवक दोनों ही अपेक्षा से कम होने के कारण सिंचाई के लिए पानी छोड़ना संभव नहीं हो पाया। इस स्थिति ने कावेरी डेल्टा के किसानों की चिंताएं बढ़ा दी हैं। समय पर पानी नहीं मिलने से कुरुवई फसल की बुवाई प्रभावित हो सकती है, जिससे उत्पादन में कमी आने की आशंका है। कृषि विशेषज्ञों का मानना है कि यदि जल पर्याप्त जल उपलब्ध नहीं हुआ तो इस्का अलर केवल किसानों पर ही नहीं, बल्कि खेती से जुड़े हजारों कृषि मजदूरों के रोजगार पर भी पड़ेगा। आमतौर पर दक्षिण-पश्चिम मानसून के सक्रिय होने के बाद केरल और कर्नाटक के कावेरी जलप्रणाल क्षेत्रों में अच्छी बारिश होती है। इसके परिणामस्वरूप कर्नाटक का कर्बिनी बांध भरता है और अतिरिक्त पानी कावेरी नदी के किनारे बंध का वर्तमान जलस्तर 31.84 फीट दर्ज किया गया है। बांध में पानी की आवक 2,446 क्यूसेक है, जबकि कुल जल भंडारण 6.08 टीएमसी है। ऐसे में निकट भविष्य में मेट्टूर बांध को पर्याप्त जल मिलने की संभावना भी कम दिखाई दे रही है। पिछले वर्षों के आंकड़े स्थिति की गंभीरता को और स्पष्ट करते हैं। वर्ष 2023 में मेट्टूर बांध का जलस्तर 103.35 फीट होने के कारण 12 जून को बांध का जलस्तर के लिए पानी छोड़ दिया गया था। हालांकि बाद में कमजोर मानसून के चलते जलस्तर तेजी से घटा गया और 10 अक्टूबर को सिंचाई के लिए पानी की आपूर्ति रोकनी पड़ी थी।





कंगना ने बताया कि 'भारत भाग्य विधाता' में क्यों निभाई नर्स की भूमिका

कंगना रनौत की फिल्म 'भारत भाग्य विधाता' 26/11 मुंबई आतंकी हमलों के दौरान कामा अस्पताल में घटी सच्ची घटनाओं पर आधारित है। यह फिल्म नर्स की बहादुरी की अनसुनी कहानी को बताती है। इस फिल्म में कंगना ने एक नर्स की भूमिका निभाई है। अपनी फिल्म और अपने किरदार को लेकर कंगना ने कई बातों का खुलासा किया है।

कंगना रनौत ने फिल्म 'भारत भाग्य विधाता' में एक नर्स की भूमिका निभाई है। एएनआई से बातचीत के दौरान इस फिल्म में नर्स की ड्रेस को लेकर कंगना ने कहा, 'नर्सों की वर्दी बहुत ब्रिटिश लगती है, उन्हें नर्सों की अपनी पसंद के अनुसार भारतीय रूप दिया जाना चाहिए।' कंगना रनौत ने बताया कि उन्होंने 'भारत भाग्य विधाता' में एक नर्स की भूमिका क्यों निभाई है। कंगना ने कहा, 'अस्पताल के कर्मचारियों ने देश के लिए दृढ़ता दिखाई। एक नर्स अजमल कसाब की पहचान करने में महत्वपूर्ण गवाह बनकर उभरीं।' इसके साथ ही कंगना ने पीएम मोदी की 'भारत भाग्य विधाता' की योजना के बारे में भी ख़ास बात बताई है। कंगना रनौत ने कहा, 'भारत भाग्य विधाता 26/11 हमलों की एक अनकही वीरता की कहानी है।' इसके साथ ही कंगना ने बताया कि उस दौरान गोलियों और अफरा-तफरी के बीच, नर्सों ने 20 बच्चों को जन्म देने में मदद की थी। फिल्म में कंगना रनौत ने एक नर्स की भूमिका निभाई है। उनके साथ गिरिजा ओक भी एक नर्स के किरदार में हैं। इस फिल्म को मनोज तापड़िया ने लिखा और निर्देशित किया है। 'भारत भाग्य विधाता' एक पैन-इंडिया फिल्म है। कंगना इस फिल्म की निर्माता भी हैं। कंगना और गिरिजा के अलावा फिल्म में रिमता तांबे, सुहिता थाटे, आशा शेलार, प्रिया बेडे, ईशा डे, रसिका अघासे, अमृता नामदेव, अदित्य मिश्रा और जाहिद खान भी अहम किरदारों में हैं।



विजय की फिल्म में दिखेंगी मालविका

मालविका मोहनन इन दिनों अपने करियर के सबसे व्यस्त दौर से गुजर रही हैं और एक साथ कई बड़ी फिल्मों पर काम कर रही हैं। हाल ही में मिली जानकारी के अनुसार वह इन दिनों चेन्नई में निर्देशक त्यागराजन कुमाराराजा की बहुमतीशित फिल्म 'पॉकेट नॉवल' की शूटिंग में व्यस्त हैं, जिसमें उनके साथ विजय सेतुपति मुख्य भूमिका में नजर आएंगे। बताया जा रहा है कि मालविका केवल 'पॉकेट नॉवल' की शूटिंग ही नहीं कर रही हैं, बल्कि इसके साथ-साथ एक अन्य अभी तक घोषित नहीं की गई फिल्म पर भी काम कर रही हैं। व्यस्त कार्यक्रम के बावजूद वह अपने सभी प्रोजेक्ट्स को लेकर बेहद उत्साहित हैं और पूरी लगन के साथ शूटिंग में जुटी हुई हैं। सूत्रों के अनुसार चेन्नई में चल रहे लगातार फिल्मों के बीच मालविका दोनों फिल्मों के काम को संतुलित कर रही हैं, जो उनके पेशेवर समर्पण और मेहनत को दर्शाता है।

ओटीटी के बजाय थिएटर फिल्म करना चाहती हैं शिल्पा शेठ्टी

बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेठ्टी इन दिनों अपने फिल्मी फैसलों को लेकर काफी साफ और सख्त नजर आ रही हैं। ओटीटी के बढ़ते दौर के बीच उन्होंने खुलकर बताया कि अब वो हर प्रोजेक्ट नहीं करती, बल्कि बहुत सोच-समझकर चुनती हैं।

काम में कोई 'कंप्रोमाइज' नहीं करना चाहती
इंटरव्यू में शिल्पा ने साफ शब्दों में कहा कि अब वो अपने काम में कोई 'कंप्रोमाइज' नहीं करना चाहती। उनका मानना है कि इतने साल इंस्ट्रुटी में काम करने के बाद अब वही करना चाहिए जो दिल से सही लगे और स्क्रीन पर दिखने का कोई मजबूत कारण हो।

थिएटर फिल्म करना चाहती हैं शिल्पा

उन्होंने यह भी माना कि आजकल फिल्म इंडस्ट्री में बड़ा बदलाव आया है। कई मेकर्स अब थिएटर के बजाय ओटीटी को सुरक्षित विकल्प मानते हैं, क्योंकि वहां रिस्क कम होता है। लेकिन शिल्पा का नजरिया थोड़ा अलग है। वो अब ऐसी फिल्म करना चाहती हैं, जो थिएटर में रिलीज हो। उन्होंने कहा, 'मेरे बच्चों ने मुझे थिएटर में नहीं देखा है। इसलिए मैं एक थिएटर फिल्म करना चाहती हूँ। मेरे

बेटे ने 2023 में सुखी देखी थी, लेकिन वो प्रीव्यू थिएटर में थी। मैं चाहती हूँ कि मुझे ऐसी फिल्म मिले, जैसी हम पहले बनाया करते थे।

काफी सोचकर प्रोजेक्ट चुनती हैं शिल्पा

शिल्पा ने बताया कि उन्होंने कई बड़ी फिल्मों को भी मना किया है, लेकिन उन्हें अपने फैसलों का कोई पछतावा नहीं है। उन्होंने कहा उनके लिए ऐसा या बड़ा प्रोजेक्ट नहीं, बल्कि काम की क्वालिटी ज्यादा मायने रखती है। शिल्पा शेठ्टी ने इंस्ट्रुटी में खूब पहचान बनाई है। वे आज 51 वर्ष की हो गई हैं। अपनी फिटनेस के लिए भी वे खूब जानी जाती हैं। शिल्पा के वर्क फ्रंट की बात करें तो वे क्वीक रियलिटी शो 'मां है ना' होस्ट करती दिखेंगी।

डेली सोप में काम करना आसान नहीं, लेकिन यही संघर्ष मुझे मजबूत बनाता है

मुंबई टीवी शो में हर रोज नए एपिसोड लाने के लिए कलाकारों और पूरी टीम को कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। कई बार घंटों शूटिंग करनी पड़ती है, कम समय में डायलॉग्स याद करने पड़ते हैं और अलग-अलग इमोशनल वाले सीन्स को तुरंत निभाना पड़ता है। ऐसे माहौल में काम करना किसी चुनौती से कम नहीं होता। इस पर बात करते हुए टीवी अभिनेत्री नेहा हरसोरा ने डेली सोप में काम करने के अपने अनुभव साझा किए। उन्होंने बताया कि यह सफर आसान नहीं है, लेकिन यही मुश्किलें उनके काम को खास बनाती हैं।

नेहा हरसोरा ने कहा, डेली सोप में काम करना बेहद चुनौतीपूर्ण होता है। यह काम कई बार शारीरिक और मानसिक रूप से थका देने वाला होता है। जिंदगी में जो चीजें आसानी से मिल जाती हैं, उनमें वह संतुष्टि नहीं होती, जो कड़ी मेहनत के बाद मिलने वाली सफलता में होती है। अभिनय का पेशा कभी भी आसान नहीं रहा है और शायद यही वजह है कि यह मुझे इतना पसंद है।

अपने अनुभवों को साझा करते हुए नेहा ने कहा, कई बार शूटिंग के दौरान कलाकारों को सीन शुरू होने से कुछ मिनट पहले ही लाइन्स दिए जाते हैं। ऐसे में उन्हें तुरंत याद करना और बिना गलती के कैमरे के सामने प्रस्तुत भी करना पड़ता है। कई बार ऐसा भी होता है कि एक सीन में कलाकार को रोना होता है और कुछ ही देर बाद दूसरे सीन में हंसना पड़ता है। इतनी जल्दी इमोशन बदलना आसान नहीं होता, लेकिन डेली सोप का हिस्सा होने के कारण कलाकारों को यह सब करना पड़ता है। नेहा ने कहा, डेली सोप का शूटिंग शेड्यूल इतना व्यस्त होता है कि कलाकार अपने घर से ज्यादा समय सेट पर

बिताते हैं। सुबह से लेकर देर रात तक शूटिंग चलती रहती है। कई बार परिवार के साथ समय बिताने का मौका भी बहुत कम मिलता है। जब किसी ने अभिनेता बनने का सपना चुना है, तो उसे इस तरह की चुनौतियों के लिए भी तैयार रहना चाहिए।

अभिनेत्री ने कहा, मुझे सेट पर बिताया गया हर पल पसंद है। कैमरे के सामने खड़े होकर एक्टिंग करना, लाइन्स याद करना और सही इमोशन के साथ दर्शकों तक पहुंचाना मुझे खुशी देता है। एक्टिंग मेरे लिए सिर्फ रोजगार का जरिया नहीं है, बल्कि एक ऐसा जुनून है जिसे मैं पूरे दिल से जीती हूँ। हर दिन का काम मुझे यह याद दिलाता है कि मैंने एक्टिंग की दुनिया में आने का फैसला क्यों किया था। नेहा ने फिल्मों और वेब सीरीज में काम करने वाले कलाकारों का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा, फिल्मों और वेब सीरीज में कलाकारों को किरदार समझने, भाषा पर काम करने और रिसर्च करने के लिए पर्याप्त समय मिल जाता है। कई बार वर्कशॉप भी आयोजित की जाती हैं, जिससे कलाकार अपने किरदार में और बेहतर ढंग से ढल सकें। लेकिन डेली सोप की दुनिया बिल्कुल अलग होती है।



अच्छी स्क्रिप्ट मिले, तो मैं जर्मन भाषा में भी फिल्म कर लूंगा

अदिति शेष इन दिनों अपनी एक्शन-ड्रामा फिल्म 'डकैत: एक प्रेम कथा' को लेकर चर्चा में हैं। 'क्षणम्', 'गुंडावारी' और 'मेजर' जैसी फिल्मों के जरिए अपनी अलग पहचान बना चुके शेष ने इस फिल्म के माध्यम से एक बार फिर दर्शकों के सामने नई कहानी पेश करने की तैयारी की है। बातचीत में अदिति शेष ने अपनी आगामी से अपने जुड़ाव और इसके अन्य पहलुओं पर चर्चा की। मेरे लिए 'डकैत' का उद्देश्य केवल एक्शन दिखाना नहीं था 'डकैत' मूल रूप से सबसे पहले एक प्रेम कहानी है। मैं हमेशा इसी तरह देखता हूँ कि यह प्यार की कहानी में बुना गया एक्शन है, न कि एक्शन की कहानी में जोड़ा गया प्यार। अगर आपने फिल्म का गाना 'रुबरू' सुना है, जिसे फहीम अब्दुल्ला ने आवाज दी है, तो उसमें एक बेहद सादगी भरा,

रुहानी और पुराने दौर के प्रेम का एहसास मिलता है। यह वैसी ही भावनाओं को दर्शाता है, जैसा कभी पुराने उपन्यासों या पिछली पीढ़ियों की प्रेम कहानियों में देखने को मिलता था। फिल्म का मूल विचार यही था कि जब इतने सरल, पवित्र और भावनात्मक प्रेम के बीच अचानक हिंसा और तीव्र एक्शन प्रवेश करता है, तो पुरा परिवेश किस तरह बदलता है। यही विरोधाभास इस कहानी की सबसे बड़ी ताकत है। मेरे लिए 'डकैत' का उद्देश्य केवल एक्शन दिखाना नहीं था, बल्कि यह दिखाना था कि भावनात्मक रूप से हमेशा इतने सख्त कि यह प्यार की कहानी में असर डालते हैं। यही तत्व फिल्म को अलग, बड़े कैमवास वाली और विश्वसनीय बनाते हैं। मेरा नजरिया हमेशा से स्पष्ट रहा है। मैंने तब भी कहा था कि अगर मुझे अच्छी स्क्रिप्ट मिले, तो मैं जर्मन भाषा में भी फिल्म करने के लिए तैयार हूँ। मेरे लिए भाषा नहीं, बल्कि कहानी महत्वपूर्ण है। 'मेजर' के बाद मुझे हिंदी और साथ ही फिल्म इंडस्ट्री से 4-5 बड़ी वॉर फिल्में और बायोपिक्स ऑफर हुई थीं, लेकिन मेरे भीतर का लेखक मुझे बार-बार रोक रहा था। मुझे लगा कि मेजर संदीप उन्नीकुण्णन का किरदार निभाने के तुरंत बाद किसी दूसरी सीनिक-आधारित कहानी का हिस्सा बनना सही नहीं होगा। मैं उनके माता-पिता की भावनाओं और उनकी यादों के प्रति ईमानदार रहना चाहता था। मेरे लिए हमेशा वही कहानी मायने रखती है, जो भीतर तक प्रभावित करे।

तीन दशक से एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री पर है एकता कपूर का राज



भारतीय टेलीविजन की बात हो और एकता कपूर का नाम न आए, ऐसा शायद ही कभी हो। पिछले तीन दशकों में अगर किसी एक शख्स ने छोटे पर्दे की दुनिया को सबसे ज्यादा प्रभावित किया है, तो वह है एकता कपूर। उन्हें यू ही 'कॉन्ट वीन' नहीं कहा जाता। उन्होंने सिर्फ टीवी शो नहीं बनाए, बल्कि ऐसे किरदार, कहानियाँ और ट्रेड्स गाढ़े जो लोगों की जिंदगी और बातचीत का हिस्सा बन गए।

एकता कपूर ने उस दौर में टेलीविजन की दुनिया में कदम रखा, जब मनोरंजन के विकल्प बेहद सीमित थे लेकिन उन्होंने भारतीय दर्शकों की नब्ज को जिस तरह समझा, उसने उन्हें बाकी निर्माताओं से अलग खड़ा कर दिया। उनकी कंपनी बालाजी टेलीफिल्म्स ने भारतीय टेलीविजन को ऐसे शो दिए, जिन्होंने टीआरपी के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए और घर-घर में अपनी पहचान बनाई। एकता कपूर के धारावाहिकों के किरदार इतने लोकप्रिय हुए कि लोग उन्हें अपने परिवार का हिस्सा मानने लगे। इसका सबसे बड़ा उदाहरण था 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' में मिहिर विरानी की मौत। यह सिर्फ एक कहानी का मोड़ नहीं था, बल्कि एक राष्ट्रीय घटना बन गई थी। दर्शकों ने विरोध किया, भावुक हुए और आखिरकार शो के निर्माताओं को मिहिर को वापस लाना पड़ा। यह भारतीय टेलीविजन के इतिहास के सबसे चर्चित पलों में से एक बन गया। इसी तरह 'कसौटी जिंदगी की' की कोमोलिका को कौन भूल सकता है? उर्वशी ढोलकिया का यह किरदार सिर्फ एक खलनायिका का नहीं था, बल्कि एक पोप कल्चर आइकॉन बन गया। उनकी

स्टाइलिश बिंदी, ड्रामेटिक एंट्री और बेकग्राउंड म्यूजिक ने ऐसा असर छोड़ा कि आज भी कोमोलिका का नाम लेते ही वह छवि आंखों के सामने आ जाती है। एकता कपूर ने सिर्फ ड्रामा नहीं रचा, बल्कि टैंड भी बनाए। 'कुटुंब' और 'कहीं तो होगा' जैसे शो ने रोमांस को नए अंदाज में पेश किया। ऑफिस रोमांस की कहानियों ने युवाओं के बीच एक नया क्रैज पैदा किया। वहीं 'नागिन' के जरिए उन्होंने सुपरनेचुरल फिक्शन को मुख्यधारा में ला खड़ा किया। मौनी रॉय का इच्छाधारी नागिन वाला किरदार इतना लोकप्रिय हुआ कि यह शो भारतीय टेलीविजन की सबसे सफल फ्रेंचाइजी में शामिल हो गया।

एकता कपूर की सफलता सिर्फ उनके शोज तक सीमित नहीं है। उन्हें इंडस्ट्री की सबसे बेहतरीन 'टैलेंट स्पॉटर' भी माना जाता है। उन्होंने कई ऐसे कलाकारों को मौका दिया, जो आगे चलकर बड़े सितारे बने। विद्या बालन को शुरुआती पहचान 'हम पांच' से मिली। आज वही विद्या भारतीय सिनेमा की सबसे सम्मानित अभिनेत्रियों में गिनी जाती है। दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत को भी घर-घर तक पहुंचाने का श्रेय काफी हद तक एकता कपूर को जाता है। 'पवित्र रिश्ता' के मानव के रूप में उन्होंने करोड़ों दर्शकों का दिल जीता और यहीं से उनके फिल्मी करियर की मजबूत नींव पड़ी। इसी तरह मौनी रॉय, प्रावी देसाई, अनिता हसनंदानी, राधिका मदान और कई अन्य कलाकारों को भी एकता कपूर के मंच से पहचान मिली। यही वजह है कि इंडस्ट्री में उन्हें सिर्फ निर्माता नहीं, बल्कि 'स्टारमेकर' भी कहा जाता है।

एकता कपूर की एक और खासियत यह रही कि उन्होंने समय के साथ खुद को लगातार बदला। जब टीवी का दौर चरम पर था, तब उन्होंने छोटे पर्दे पर राज किया और जब डिजिटल प्लेटफॉर्म का दौर आया तो उन्होंने वेब कॉन्टेंट की दुनिया में भी अपनी मजबूत मौजूदगी दर्ज कराई। वह दर्शकों की बदलते पसंद को समझती रही और उसी के अनुसार कॉन्टेंट तैयार करती रही। उनकी मेहनत और योगदान को देश-दुनिया में कई बड़े सम्मान मिले हैं। पद्म श्री के साथ ही एकता कपूर को बिजनेस, मीडिया और मनोरंजन जगत के कई प्रतिष्ठित पुरस्कारों से नवाजा जा चुका है।